[Shri A. B. A. Ghani Khan Chaudhuri]

I shall endeavour to make up the reduction by further stricter control over expenditure and carriage of larger volume of traffic. The House will appreciate that I have done the maximum possible keeping in view the overall constraints.

Before I sit down, let me thank all the hon. Members and the Chair for the patient hearing given to me and for the cooperation extended to me.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER: There is no time now.

SHRI ERA ANBARASU (Chengalpattu): I have requested the hon. Railway Minister to change the name of the Gran Trunk Express as Bharati Express. It does not involve any financial commitment. I request the hon. Railway Minister to consider my request.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You write to him. He is a lion-hearted man.

SHRI ERA ANBARASU: I have made a request to change the name of the Grand Trunk Express as Bharati Express. It does not involve any financial commitment..

MR. SPEAKER: Please sit down. You give him in writing.

MR. ERA ANBARASU: I request the hon. Railway Minister to consider my request. It is a long-pending request.

MR. SPEAKER: Please sit down. We have to take up the next discussion.

13.32 hrs.

DISCUSSION *RE*: SITUATION IN PUJAB—*Contd.*

MR. SPEAKER: We now take up further discussion regarding the siiuation in Punjab which we had already started. Mr. Vajpayee was in possession of the floor. But before we start..

AN HON. MEMBER: After lunch.

MR. SPEAKER: No lunch. It is better. It keeps you more smart and fit.

We have now full two hours, from 1.30 to 3.30 p.m. I shall allot ten minutes to each as decided by the Business Advisory Committee and two minuties more to Mr. Vajpayee..

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): Five minutes more.

MR. SPEAKER: All right. Remember this: no Member should transgress the ten-minute limit. I shall give the first bell after eight minutes. (*Interruptions*) Let us start now.

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के पिछले अधिवेशन में मैं पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में एक चर्चा आरम्भ करना चाहता था । लेकिन, वह चर्चा उस समय नहीं हो सकी । यह तय हुआ कि हम अगले स ं में पंजाब के बारे में विचार करेंगे । यह बात 5 नवम्बर 1982 की है । आज जब हम पंजाब के बारे में बहस कर रहे हैं तो 1982 का साल पीछे छूट गया है, 1983 की चुनौतियां हमारे सामने हैं । पांच नवम्बर के बाद आज चार मार्च को चर्चा हो रही है । लगभग चार महीने बीत गए । इन चार महीनों में रावी और व्यास में से बहुत सा पानी बह गया है । काल का प्रवाह निरन्तर चलता रहता है । पानी जब तक बहता रहता है तब तक पानी साफ रहता है । जब पानी जोहड़ का रूप ले लेता है, उस का बहना रुक जाता है तो वह गन्दगी में बदल जाता है और सड़ान्ध पैदा करता है । 5 नवम्बर, 1982 को मुझे आशा थी कि जब हम अगले सत्र में मिलेंगे और पंजाब को चर्चा करेंगे तो पंजाब के सवाल बातचीत के रास्ते से हल हो चुके होंगे और गृह मंत्री हम कोई अच्छी खबर देंगे । लेकिन आज जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो पंजाब को

स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती हुई दिखाई देती है । बातचीत में एक गतिरोध पैदा हो गया है ।

पंजाब हमारा सीमा प्रदेश है । पंजाब के पार अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति चिन्ता पैदा करती है । यह स्वाभाविक है कि ऐसी हालत पंजाब के सवाल मिल बैठ कर हल किये जायं। कोई भी पक्ष ऐसा रवैया न अपनाये जिससे विद्यमान तनावों में वृद्धि हो, विभिन्न समुदायों में भेद बढ़े और पंजाब कमजोर हो, और पंजाब की कमजोरी के साथ सारा देश भी कमजोर हो ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 महीने में दो महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं । एक तो यह हुआ है कि विरोधी दलों के नियंत्रण पर अकाली पार्टी ने त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लेना स्वीकार किया। केन्द्र सरकार भी गतिरोध के बिन्दु पर पहुंचने के बाद इसके लिए प्रस्तुत थी । त्रिपक्षीय वार्ता के कई दौर चले। उस पर कुछ कहने से पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि अगर शुरू से ही पंजाब के और देश के भी अन्य दलों को भी तस्वीर में रखने की कोशिश की जाती तो शायद मामला इतना लम्बा नहीं चलता। पहले तो बातचीत इस तरह से होती रही मानो पंजाब के सवाल कांग्रेस पार्टी अकाली पार्टी के दिपक्षीय मामले हैं, और दलों का चाहे पंजाब के हों, चाहे शेष भारत के ,उन मामलों से कुछ भी लेना देना नहीं है, गाहे बगाहे उनसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन उन्हें वार्ता में भागीदार नहीं बनाया जायगा । असम के बारे में भी ऐसा ही हो चुका है । मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी को अब ईमानदारी से यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो राष्ट्रीय प्रश्न है उन का वह अकेले समाधान ढूंढने की शक्ति नहीं रखती है, अब यह उसके बूते की बात नहीं रही है । उससे और दलों को भी साथ ले कर चलना पड़ेगा । समस्याओं को हल करने के लिये यह आवश्यक भी है । लेकिन इसमें देर होने से बात बिगड़ती है ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल): हमारी फराखदिली को कमजोरी न समझो। यह हमारी उदारता है आपको कान्फीडेंस में लिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: तो आपके निमंत्रण पर हम हिस्सा ले रहे हैं यह भी हमारी कमजोरी नहीं है । हमारी भी उदारता है । लेकिन ऐसी उदारता अगर पहले ही दिखा देते तो आपको मजबूरी का आभास नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय, जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई उसमें से कुछ अच्छी चीजें निकली हैं, पहले मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा । वार्ता के परिणामस्वरूप मतभेद घटे हैं, भ्रमों के बादल कुछ छटे हैं, तीनों पक्षों ने एक दूसरे की स्थिती को, रवैये को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की है और एक सद्भावना का वातावरण बना है ।

मुझे संतोष है कि अकाली दल के प्रतिनिधियों ने त्रिपक्षिय वार्ता के दौरान राजस्थान और हिमाचल के कुछ क्षेत्रों पर अपने दावे छोड़ दिये । पहले अकाली पार्टी अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा और जीन्द के पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में शामिल करने की मांग करती थी, अब उनकी मांग चण्डीगढ़, अबोहर, फाजिल्का तथा सीमावर्ती क्षेत्र तक सीमित है । मैं इसे एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं और इससे क्षेत्र संबंधी विवाद को हल करने में आसानी होगी ।

त्रिपक्षीय वार्ता की दूसरी उपलब्धि यह है कि अकाली दल को वहां बैठकर जरूर इस बात की अनुभूति हुई होगी कि आनन्दपुर साहब का प्रस्ताव आज जिस रूप में है, उसे अन्य दलों के लिये स्वीकार करना बहुत कठिन है । पहले अकाली दल इस बात पर तुल रहा था कि केन्द्र और राज्य के संबंध के पुनरावलोकन के लिए जो भी कमेटी या समिति बने उसकी टर्म्स आफ रैफरेंस में आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव का उल्लेख जरूर होना चाहिये, लेकिन बाद में उसके समझाने-बुझाने पर वे मान गये कि प्रस्ताव का उल्लेख करना जरूरी नहीं है । मैं समझता हूं कि यह भी एक सही दिशा में हम आगे बढ़े हैं

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

और इसे भी त्रिपक्षीय वार्ता की एक उपलब्धि माना जा सकता है ।

मैंने आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव का उल्लेख किया है । उस प्रस्ताव को लेकर काफी भ्रम फैला है । कुछ क्षेत्रों में चिन्ताएं भी जागी हैं, कहीं-कहीं आशंकाएं भी सिर उठा रही हैं । यह भ्रम इसलिये और बढ़े हैं कि आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव के अलग-अलग वर्शन हमें मिले, लेकिन बाद में संत लौंगोवाल जी ने जो अधिकृत वर्शन दिया है, उससे काफी भ्रम दूर हुआ है ।

हमारे अकाली मित्रों को एक बात साफ समझ लेनी चाहिये कि देश अभी तक धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों के जहरीले सिद्धान्त से पूरी तरह उबरा नहीं है । यह अनेक उपासना-पद्धतियों का देश है । यह बहु-भाषी देश है, अपनी-अपनी उपासना-पद्धति पर दृढ़ रहते हुए भी हमें भारतीय राष्ट्रीयता में अपनी अटूट निष्ठा रखनी है । इसलिये अगर धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर कोई समुदाय यह दावा करेगा कि वह अलग नशन है, अलग कौम है, उसका एक अलग संविधान होना चाहिये, तो इससे देश की एकता पर आघात होगा ।

मुझे संतोष है कि अकाली मित्रों ने, विशेषकर जो वार्ता के लिये आये थे, मेरे मित्र श्री मधु दंडवते और श्री चन्द्रजीत यादव यहां बैठे हैं, मैं वार्ता में शामिल नहीं था, हमारे पक्ष की ओर से श्री अडवाणी उपस्थित थे, उन्होंने जो रविय्या अपनाया उससे इस मामले में काफी आश्वस्त हुई है ।

दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई है कि प्रधान मंत्री ने अकाली दल की धार्मिक मांगों के बारे में एकतरफा एलान कर दिया है । अच्छा होता अगर वह एलान संसद में होता, लेकिन उन्होंने उचित समझा कि गुरूद्वारा बंगला साहब में जाकर एलान करें । हमारे कांग्रेसी मित्र कह सकते हैं कि धार्मिक मामलों की स्वीकृति का एलान धार्मिक स्थानों पर होना चाहिये, लेकिन संसद को उपेक्षित करना आवश्यक नहीं था ।

अभी तक आल इंडिया गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट बनाने के बारे में जो चौथी मांग है उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी पहले तय नहीं कर पाई कि धार्मिक मांगों को अलग करें या उन्हें राजनीतिक मांगों के साथ जोड़ें । पहले विचार था कि एक पैकेज होगा, अब पैकेज का सुझाव छोड़ दिया, एकतरफा एलान कर दिया । दो मांगे बची हुई हैं । एक पानी के बारे में है । अगर अकाली दल शुरू से इस बात पर बल देता कि पंजाब को आज जितना पानी मिल रहा है, उतना मिलता रहना चाहिये, कम नहीं होना चाहिये, यह सवाल केवल सिखों का सवाल नहीं है, सारे पंजाब का सवाल है तो न केवल उन्हें पंजाब के राजनीतिक दलों का ही समर्थन मिलता बल्कि पंजाब से बाहर भी बहुत सहानुभूति से उनकी बात सुनी जाती । पंजाब का किसान जो बड़ी मेहनत के साथ पैदा करता है वह सारे देश के लिए पैदा करता है । पंजाब के किसान की कठिनाई को भुलाकर कोई भी हल ढूंढ़ा जाए, तो स्वाभाविक है पंजाब में इसको लेकर बेचैनी पैदा होगी ।

मुझे पता लगा है और मैं सेठी जी से पूछना चाहूंगा क्या यह सच है कि पानी के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय वार्ता में एक स्टेज पर अकाली मित्रों ने यह मान लिया था कि इस में से राजस्थान को हटा दिया जाएगा । क्या यह मान लिया था कि 1955 के समझौते के अनुसार राजस्थान को जो पानी मिलता है, वह मिलता रहेगा और उस समझौते के अन्तर्गत राजस्थान को जो अधिकार प्राप्त है, राजस्थान उन अधिकारों का पूरी तरह से उपभोग करता रहेगा ? क्या यह भी सच है कि यह तय हुआ था कि पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के आवंटन के सवाल को इन्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, 1956 के अन्तर्गत ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जायेगा लेकिन ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक हरियाणा और पंजाब, दोनों दिसम्बर, 1981 के समझौते के अनुसार पानी प्राप्त करते रहेंगे और इस बीच में सतलुज-यमुना लिंक कैनाल को पूरा किया जायेगा, दो साल के भीतर, तथा उसे और भी चौड़ा किया जाएगा ? मैं जानना चाहता हूं क्या

पानी के सवाल पर एक आम सहमति हो गई थी और अकाली मित्र राजस्थान को छोड़ने के लिए तैयार थे ? यदि हां तब फिर गतिरोध क्यों पैदा हुआ ?

सतलुज-यमुना लिंक कैनाल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अब अकाली दल को भी उसके बनाने पर आपत्ति नही है लेकिन पंजाब की सरकार उसे बना नहीं रही है । उसे बनाने का काम आगे बढ़ाया जा सकता है ।

दूसरी बात है क्षेत्रों के बारे में प्रधान मंत्री ने चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में जो एवार्ड दिया था उसके हिसाब से चण्डीगढ़ पंजाब को चला जाना चाहिये था । मैं उन मित्रों से सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि चन्डीगढ़ के साथ अबोहर और फाजिलका जुड़ा हुआ है । मेरे पास समय नहीं है कि मैं एवार्ड से उद्धत कर सकूं । अब अकाली दल यह कह सकता है कि हमें प्रधान मंत्री का एवार्ड मंजूर नहीं है, हम ऐसे मामले में एक न्यायिक एवार्ड चाहते हैं । पानी के बारे में वे यह कह भी रहे हैं । लेकिन चण्डीगड़ के सम्बन्ध में अकाली दल कहता है कि चण्डीगढ़ उसे दे दो, फाजिलका और अबोहर जो एबार्ड के हिसाब से हरियाणा को जाने चाहिए थे वे हरियाणा को नहीं जायेंगे, अगर कुछ गांवों को इधर-उधर करना है तो उसके बारे में कमीशन बनाया जा सकता है। मैं चण्डीगढ़ को बांटने के खिलाफ हूं। चन्डीगढ़ अपने में एक इकाई है। चण्डीगढ़ एक प्रदेश की राजधानी के रुप में निर्मित हुआ है । चण्डीगढ़ को बाटने की बात नहीं करनी चाहिए । हरियाणा के नेताओं को इस मामले में विश्वास में लेकर उनसे स्वीकार करा लेना चाहिए कि वे अपनी राजधानी अलग बनायें और उसके लिए केन्द्र से रुपया लें । लेकिन पानी के सवाल पर और क्षेत्रीय सवाल पर कोई भी फैसला ऐसा नहीं हो सकता जो हरियाणा और राजस्थान के लोगों की इच्छा के खिलाफ उनपर थोप दिया जाए । मुझे अकाली मित्रों से शिकायत है कि अगर वे पंजाब के पानी और क्षेत्र के सवालों को सर्वदलीय सवाल बनाकर आगे बढ़ते, राजनीतिक सवालों को धार्मिक रूप न देते और धार्मिक मामलों को साम्प्रदायिक रूप न देते तो आज पंजाब एक आवाज में बोलता, केन्द्र को भी उसकी आवाज सुननी पड़ती मगर आज पंजाब की आवाज बिखर गई है, पंजाब की आवाज टूट रही है, पंजाब पंजाब के नाते नहीं बोल रहा है, इसके लिए अकाली दल भी जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी भी कम जिम्मेदार नहीं है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, आखिर सत्ता किसके हाथ है ? कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पंजाब में किसके ऊपर है ? कौन पंजाब की परिस्थिति कम करके बताता रहा है। कौन अवैध हथियारों को रखने वालों को गिरफतार करने में विफल रहा है? दिल्ली में अवैध हथियार लेकर लोग घूमते रह, केन्द्रीय सरकार ने कुछ नहीं किया । आज भी पंजाब में हत्या की घटनायें हो रही हैं। उसके लिए किसको दोष दिया जाएगा। दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दखल दिया, मैं पहले भी उसकी निन्दा कर चुका हूं, मैं फिर निन्दा करना चाहता हूं। साम्प्रदायिकता की काट उससे बड़ी साम्प्रदायिकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: दो सवाल हैं ।....

(व्यवधान)...

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : जनता पार्टी के राज में अकालियों से समझौता आपने किया । उनका हौसला नहीं बढ़ाया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देने को तैयार हूं । हमने समझौता किया तब पंजाब में शान्ति थी। तब खालिस्तान की आवाज नहीं उठी थी ।

...((**व्यवधान**)...

आचार्य भगवान देव : सत्ता में से आप गए हैं, उसके बाद आप प्रोत्साहन दे रहे हो ... **(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लेकिन पंजाब के उग्र पंथियों को अगर कोई दिल्ली में लाया है, तो कांग्रेस पार्टी लाई है ।

आचार्य भगवान देव : पंजाब की बात करते हुए दिल्ली के चुनाव की बात क्यों करते हैं । ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : जवाब आ जाएगा । जब तुम्हारा टर्न आ जाएगा, तब बोल देना ।

आचार्य भगवान देव : इस तरह से सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

. . . (**व्यवधान**) . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: दिल्ली की गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के लिए जो कानून बना, उसमें पहले मैट्रिक पास होना जरूरी था । बाद में मैट्रिक पास होना जरूरी नहीं रहा क्यों ?

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : अब मैट्रिक फेल कम्पलसरी करेंगे । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह राजनीति नहीं है । उग्रवादी तत्वों को किसने बढ़ावा दिया ? . . . (**व्यवधान**) . . . अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करना चाहता हूं ।

आचार्य भगवान देव : अकालियों को प्रोत्साहन आपने दिया । भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने दिया । पंजाब में स्थिति बिगाड़ने वाले आप हैं और आपकी पार्टी है । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अकाली लोगों को गोली मार दिया जाएगा ।

आचार्य भगवान देव : कौन कहता है गोली मार दो । उनको प्रोत्साहन आपने दिया । आपकी पार्टी ने दिया । . . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं, आप लोग ।

. . . (**व्यवधान**) . . .

श्री राम विलास पासवान: जो सही है, सही है । जो गलत है, वह गलत होगी . . . (**व्यवधान**) . . . सारी चीज स्पायल कर रहे हैं । . . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं ।

. . . (**व्यवधान**) . . .

आचार्य भगवान देव: सदन को गुमराह कर रहे हैं । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं गरमा गर्मी में अपना भाषण समाप्त नहीं करना चाहता ।

आचार्य भगवान देव : आप कर क्यों रहे हैं । टू-दि-प्वाइंट बोलिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तय करेंगे–टू-दि-प्वाइंट ? कौन करेगा ? . . . (**व्यवधान**) . . . अध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। यह किस तरह से ** कर रहे हैं । . . . . . . (**व्यवधान**) . . .

आचार्य भगवान देव : आप क्षेत्रीय पार्टियों को प्रोत्साहन दे रहे हो ।

PROF. MADU DANDAVATE: Sir, who is conducting the House? He has the temerity to challenge a senior leader of a party.

. . . (**व्यवधान**) . . .

श्री गिरधारी लाल व्यास : ** –बात करते हैं ।

आचार्य भगवान देव : आप गुण्डों को प्रोत्साहन दे रहे हो । असम में प्रोत्साहन दे रहे हो । अराष्ट्रीय तत्वों को आप प्रोत्साहन दे रहे हो । क्षेत्रीय पार्टियों को आप प्रोत्साहन दे रहे हो . . . (**व्यवधान**) . .

श्री राम विलास पासवान: प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछते हो। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : बैठिए, आपको क्या पता है । . . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं चुप करके बैठते हैं । भगवान के लिए आप बैठ जाइए । मत इन्टरप्ट करिए ।

. . . (**व्यवधान**) . . .

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष जी, मर्यादा के अन्दर बोलते हैं, तो हमें कुछ नहीं कहना है । मर्यादा के बाहर जायेंगे, तो मैं बोलूंगा । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इनकी बड़ी कृपा थी, कि इन्होंने पहले कुछ नहीं कहा । हम कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे तो ये मुंह पर ताला लगायेंगे । खरी बातें सुननी पड़ेंगी । ...(**व्यवधान**)...

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, is there any rule that you must support the ruling party? If you give your ruling like that, we would like to walk out..

आचार्य भगवान देव : अकाली लोगों से आप लोग मिलते हैं ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I am not yeilding.

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बोल सकते हैं, जब आपको बोलना हो । मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं ।

...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवान : अकाली की निन्दा की तो आपको बहुत खुशी हुई । कांग्रेस की निन्दा की तो ...(**व्यवधान**)...

आचार्य भगवान देव : सदन में गुमराह क्यों कर रहे हो । उल्टी-सीधी बातें क्यों कर रहे हैं । ...(**व्यवधान**)... सारे अकाली लोगों से मिलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तुम क्यों नहीं बोल सकते। जब तुम्हें बोलना हो तो यह बात बोल देना । बीच में काटने की क्या आवश्यकता है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बोलने ही कहां देते हैं ।

एक माननीय सदस्य : पार्टी को कहिए, पार्टी आपको टाइम देगी । ...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : खत्म करिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं गरमा-गर्मी के वातावरण में अपना भाषण समाप्त नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने अपने होश-हवास ...(**व्यवधान**)... मैंने कहा क्या है ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस के सदस्य वातावरण को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं । ...(**व्यवधान**)...

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Don't show your mucle power here.

PROF MADHU DANDAVATE: He says "don't refer to the Congress Party". Then tomorrow he can say "don't refer to the Prime Minister." Who is he to give direction to Members?

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, in this way, the debates cannot continue. He is threatening us.

अध्यक्ष महोदय : हमने बोल दिया है ।

...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवान : इस बहस को गम्भीरता से चलवाइये ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, you bring the House to order I cannot speak with so much interruptions.

आचार्य भगवान देव : आप मर्यादा में बात करिये ।

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Who are you to say that? What is this? Do not show your muscle power.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने कौन सी मर्यादा भंग की है ? क्या मर्यादा का पाठ इन से पढ़ूंगा ?

श्री राम विलास पासवान : इस तरह से हाउस नहीं चलेगा ।

...(**व्यवधान**)...

MR. SPEAKER: You cannot do this all the time.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आप बतलायें, मैंने कौन सी मर्यादा तड़ी है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई मर्यादा नहीं तोड़ी है । मैंने तो यह कहा है कि आप अपने विचार व्यक्त करें और जब उन का वक्त आये तो वह अपने विचार व्यक्त करें । so simple it is. He has no right to interupt

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्यी यह विवाद को चलाने का तरीका है ? अगर मेरी बात से कांग्रेस के सदस्य सहमत नहीं हैं तो वे उस का खण्डन कर सकते हैं, तर्क रख सकते हैं । अगर कोई गलत बात कह रहा हूं तो उस की ओर इंगित कर सकते हैं । मगर टोका-टोकी का कोई मतलब नहीं है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : वह कह रहे हैं कि आप साम्प्रदायिक भावना भड़का रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जो साम्प्रदायिक-भावना।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें जो बोलना है, वह हम बोलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : देखिये-हाउस को आप नहीं चला रहे हैं मैं चला रहा हूं । आप चुप कर के बैठिये, वरना आप के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा ।

I will have to take some disciplinary action; I do not want to do it, but you are going to force me for that now.

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : ऐसी बात कहना जिससे प्रोवोकेशन हो, नहीं कहनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रोवोकेशन की बात नहीं कही है । कोई ऐसी बात नहीं कही है जिस से प्रोवोकेशन हो ।

There is no question of provocation. There is nothing of that sort.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): Sir, it is absolutely correct that no Member should interrupt the other Member, neither today, nor tomorrow. That is what each of us should follow. That is the correct thing to do. I appeal to all the Members on both the sides not to interrupt each other.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अपील से अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं । अकाली मित्रों से मेरा आग्रह है कि वे मुठभेड़ का रास्ता न अपनायें, अपने त्याग-पत्रों पर बल न दें, समझौते के द्वारा समस्याओं को हल करने के रास्ते पर चल कर फिर से बातचीत में भाग लेने के लिये तैयार हों । एक-दूसरे को समझा-बुझा कर ही हम अपनी बातें मनवा सकते हैं । अगर अकाली दल इस परिणाम पर पहुंचता है कि सरकार उस की सही बात पर भी ध्यान नहीं दे रही है तो मैं अकाली मित्रों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं -- उन्हें सारे प्रतिपक्ष का समर्थन प्राप्त होगा । लेकिन यदि प्रतिपक्ष यह अनुभव करता है कि अकाली मांगों में कुछ मांगे ऐसी हैं जिन्हें उन के वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता तो वे बातें भी अकाली मित्रों को स्वीकार करनी चाहियें । फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिये।

आज देश की एकता बनाये रखने की कितनी आवश्यकता है इस पर बल देने की जरूरत नहीं है । आसाम में जो कुछ हो रहा है उस से हम सब को गहरा धक्का लगा है । हमारी आंखें खुलनी चाहियें । पंजाब में हम साम्प्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का वातावरण बनाये रखते हुए पंजाब के सारे सवालों को मिल-बैठ कर हल करें । गुरू नानक देव जी ने कहा था---बांट कर खाओ ।

"नाम जपो, किरत करो, वांट कर खाओ ।"

मैं अकाली मित्रों से कहना चाहता हूं--- पानी भी बांट कर पियो । क्षेत्र के मामले भी इस तरह से हल करो कि किसी पक्ष को यह न लगे कि उस की पराजय हो गई है या

उस की कीमत पर कोई दूसरा पक्ष अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : ऐसी बात करो, वाजपेयी जी ।

अध्यक्ष महोदय : सिर-मूछें ऊंची कर दो ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इसी अपील के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं । मुझे विश्वास है कि आज की सारी चर्चा इसी वातावरण में होगी, खाली उस अंश को छोड़ कर ।

अध्यक्ष महोदय: देखिये, सारी बात अच्छे ढंग से चलनी चाहिए । किसी बात का भी खंडन शब्दों से होना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर नहीं ।

एक माननीय सदस्य : तर्क से होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : तर्क-वितर्क से होना चाहिए ।

SHRI R. S. SPARROW (Jullundur): Hon. Mr. Deputy-Speaker, Sir, the question is very important to India and to the world and it is to be viewed in a dispassionate manner and very coolly.

To start with, I have one observation to make that the negotiations have been going on in this regard and so much ground has been covered and still there is every opportunity and possibility for tiding over the problem to everybody's satisfaction. For that reason, we have, of course, to examine the case analytically, objectively, yet with a very cool head and a cool mind. This is my first appeal that I put up before the House as also to my own brothers—the Akali Dal and the others concerned.

Sir, what is the big-time question? The big-time question is based on misunderstanding and unfounded type of distrust. We are bound by a specified type of Constitution of India and we have come to be a very big nation to the envy of many. A propose of that we all Indians have to go about in a uniform manner and in a unified fashion.

Now, who are the Akalis? They are my brothers, my kith and kin, your borthers, your kith and kin. And may I explain who are the Sikhs? I explained that the other day also. The Sikhs, Punjabis, Haryanavis historically, rationally, philologically are of the same stock—same in everything. If I start thinking in terms of who is who, I might point out, Sir, start from anywhere you wish to, from Punjab right up to this up of Haryana and possibly quite a bit beyond, and kind of Gotra, any kind of Jat-Pat, they are from the same stem, from the same stock and, as I said, they always remained the same and it is very difficult to cut them vertically on any problem whatsoever. So, this is point number one which as a background I must tell you.

Sir, Sikhs have always been nationalist—traditionally and historically—starting from any time you like. From the period of my own beloved Gurus, they sacrified everything.

They had come right up to Delhi to hand over their heads for the sake of Bharatvarsha and for its traditions and its way of life. That is what they did. Their deals, their thinking, their preaching, their give and take, flourished everywhere round India. You take even the big holy places of the Sikhs. You take our Takhts. Outside Punjab if I may start counting, everybody will accept that their doing was for total India. If I go to Northwest side of it, Chhati Patshahi—the Sixth Guru—had an emineri holy place in Srinagar at Matan and Kharbu. You come outside Punjab and go to any place. There is the Paonta Sahib in Himachal Pradesh. If you want to drift towards Delhi six Gurus came here and they have their own sacred places where they stayed and where they sacrificed. you move towards Uttar Pradesh, you have Mitha Ratha Sahib; then Hemkund Sahib, Govind Ghat Sahib; and beyond them, there are so many *sthans* all of very holy importance to us. Go on to Madhya Pradesh, we have at Gwalior the Chhathi Patshali. Thereafter you move

[Shri R. S. Sparrow]

and you have them at Manmad and Aurangabad. We have the Huzur Sahib, one of the holy *takhts*.

Towards the east, we have the Patna Sahib. Go to Gauhati and beyond. Our Every Hindu, every Sikh, all Punjabi all revere our Gurus. Not only that. I may point out that when our Gurus were in the midst of difficulties, when they were sacrificing everything...

Gurus moved about and preached love,

लख्ते दिल कटवा दिए, चुनवा दिए दीवार में,
उफ न की इतना भरोसा था तेरे करतार में।

Here is Guru Govind Singh:

सर्व गुण संपन्न इसको पातशाही ---

He sacrificed everything. May I tell you what he stood for? He stood for secularism and he stood for mankind. Do you know who were the ones who offered themselves when he was in difficulty? Budhu Shah, a Muslim; with all his children and with all his relatives he sacrificed everything that he had.

May I give you another example? When my Guru was in difficulty, when he was being hounded out and chased, do you know who took him on their shoulders? It was Nabhi Khan and Ghani Khan. They were Muslims. They could have been given kingdoms for handing ove over the Guru. But they said: "Here is a Guru common to mankind, not only to India."

I told you about the *Panj Piaras*. They were the five beloved ones. Where did they come from? One came from Jagannath Puri, in Orissa—in the east. Another came from the western coast. *viz.* Dwarka. The third came from down South, viz. Bidar in Karnataka. Then there comes another who was ready to sacrifice himself here at the big test; he came from Hastinapur, between Mathura Ji and Delhi. And one came from Lahore in Punjab. Thus they were from different areas and backgrounds; from all over India.

These are our Sikhs, men of quality. When it came to Jalian Wala Bagh or Cama Gata Maru or when it is the question of filling jails while fighting for freedom, they did not merely act as Sikhs. No; they went to jails as nationalists and they fought for nationalism. They fought in all important battles under my command and the command of my colleagues—Hindus, Sikhs, Harijans, Charistians and Mohammedans. They fought together under different set of circumstances, in any kind of operations for rooting out from our national life some kind of disunity or the other, or some kind of bad germs.

I have only to give one example. I will wind up quickly. I speak about some kind of foreign chaps who want to put us out of gear. They want to vivisect India. Don't I understand what is our frontier? Don't I understand what is Punjab? Don't I understand what type of spies they try to win over? Some cases came out in the open. Don't I understand what type of masquerading they do? Don't I understand how money can flow and win over some people who are easy to be won over? Don't I see what is behind all these extremists, shooting innocent people indiscriminately in the streets and trying to create fiasco and chaos?

It is that type of thing by which some of them,, poor chaps, who do not understand perhaps under the garb of fundamentalism or some other type of notion, are misled. Otherwise, I see no difficulty.

In regard to demands, I have to say only two words. There are two types of prominent demands, religious demands. I shall say one word about religious demands. Atalji, it was not only at Bangla Sahib Gurdwara but even previously the hon. Prime Minister declared that Sikhs demands, religious demands were acceptable, let us work them out. Whether it was an objection from their side that they wanted to have everything collectively or some other type of misunderstanding, I am not going to indulge in that. But the demands are acceptable, whatever is reasonable. On that, I would like to raise one issue. Regarding religious demands—it is my side of it—I would like to say with candour that there has naturally to be one yardstick for India. If tomorrow, if today, we sanction any kind of religious demands to one

community, that will apply to all communities of India. There is no question about it. Therefore, we have to view the whole thing objectively and in pragmatic terms, applicable type of words should be brought in.

I am very glad that many of my Sikh brothers accept that a lot is being done to settle this issue; the ground is being well covered. My friend, Prakash Singh Badal, my friend Balwant Singh and so many other feel that we must now finish the whole tussle in some kind of a manner, in a proper manner.

Regarding administrative demand, already my friend has stated, from that side, Atalji, with a little bit of an added innovation. But that does not matter. That is to be settled by us across the table. That is my appeal also and I appreciate the appeal that has been made by Mr. Atal Bihari Vajpayee. We are bound by the Constitution of India. When we come here or when we take any kind of a legislative seat as a Minister or as a legislator or a Member of Parliament, the first thing that we do before the Speaker is that we read out an oath saying, 'I promise this. that I shall uphold the sanctity of the Constitution of India. So. anything that we do must be according to the Constitution of India. You cannot start shooting people; you cannot start doing all types of wrong things to round off the Constitution of India.

I would humbly point out to my colleagues, my friends, my relative Akalis about this Anantpur Sahib Resolution of 1973. They were in power in Punjab as also in power here with their friends. According to the Constitution, there is no reason why an amendment to any kind of Bill cannot be brought about; it can be. Even the Private Members' Bills point out that way. In their period they did not do that. I wish they would have done it. By so doing a point would have been made, whether two-thirds majority was there in Punjab or not; whether two-thirds majority would have accepted it here or not. But the point would have been, that constitutionally everything could be done. With these words, I thank you very much for giving me this opportunity.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Mr. Speaker, Sir, the situation in Punjab is extremely grave. Unless the drift is arrested, it may take a criminal turn; and it is pregnant with many possibilities. That is why we must think over the whole matter seriously.

It is a border State and Pakistan is heavily armed by the United States of America with some motive. This also we should keep in mind. When hijacking of planes and some killings started, the Akali leaders should have condemned all these things unequivocally. But I am sorry to say that they have not done it. Our party warned the Central Government about the shape of things to come, in 1981. Our central leader, Comrade Surjeet wrote a letter and our Party has also passed resolutions pointing out the danger that the extremist elements may take up the issue and try to exploit the situation to the detriment of the interests of the people of the Punjab and to the detriment of the unity of the nation. I am sorry to say that this timely warning was not heeded to by the Central Government Initially the Akalis also drew a demarcation between the demands of the extremists and the demands of the Akalis. It was Shri Prakash Singh Badal who wrote to the political parties and wanted a settlement. Now, there are some demands which are religious and there are some demands where the interests of the whole of the people of the Punjab are involved.

First of all, I come to the first demand, which is a non-religious demand, that is, re-structuring of Centre-State relations and giving autonomy to the States. So far as this demand of the Akalis is concerned, it is a democratic demand. We have been demanding this. The Marxist-Communist Party, the Communist Party, the other Left parties, the DMK, the AIDMK, today the Telugu Desam and also the Janata Party of Karnataka, all are demanding that there should be some restructuring and we want the whole Centre-State relations to be reviewed and we should grant powers to the States,

[Shri Satyasadhan Chakraborty]

more financial and administrative powers to the States. That will strengthen the States. That will strengthen the federal system and will also srengthen the Central Government. So far as this demand is concrened, there is no difference even in the Punjab among the political parties. That is a genuine and democratic demand of the people of the Punjab.

The second demand concerns water. There also, I find that the Akali leaders have also given up some of their old demands and they are trying to come to an agreement. Only one minor problem remained, when this was discussed, namely, the allocation of water in the interim period that is, pending the decision of the Tribunal. This can be settled amicably.

The third problem is territorial problem. I agree that Chandigarh should go to Punjab, but what the Akali leaders are demanding is that some villages should go to Punjab on the basis of religion, which is un-democratic. A village should be given as a unit. So, it should be on the basis of language, but not religion. In this modern period, religion should not be mixed up with politics. It should be segregated from politics and the basis of reorganisation of the States should be language. That is, the sicnetific and democratic principle on which this should be done. So, on all matters there can be agreement, based on certain principles. And it is very astonishing to see the way the negotiations are continued.

Sir, Mr. Swaran Singh was asked to negotiative on November 3, 1982. It appeared that some understanding was arrived at, but the Government tried to persuade Rajasthan and Haryana. The Akalis issued a new programme on the 4th November. They gave 15 days' time. Unfortunately these talks started on the 16th. The Central Government killed the time and the neogtiations started on 16th. Mr. Swaran Singh was out of those talks because of the reasons best known to the ruling party. From the press reports it appeared that some sort of understanding was arrived at on 18th. But it broke down. Again Akalis announced their programme of action. Again, the initiative was taken in January by appointing a Cabinet sub-committee. Akalis responded. The discussion went on. On 18 January, there was a deadlock. On 22 January, the Prime Minister called a meeting of the opposition parties where a suggestion was given for a tripartite meeting. Government agreed to that. It was called on 24th and 25th. An agreement was reached. Only a small item, allocation of water, remained. The Central Government agreed to appoint a Committee to go into the Centre—State relations. This was agreed upon. I do not know why the Central Government instead of negotiating with the Akali leaders, the Prime Minister declared unilaterally certain decisions. Why is this done? Is it to create differences in Punjab? This should not have been done. Instead of elinching the issue with the Akali leaders, why should she go to a Gurudwara in Delhi and address them? I found in the newspapers that in the lawns of her house, she addressed the Sikhs, who had gathered there, and said something. This is not the way to negotiate the term of an agreement.

My Party has been constantly opposing extremism everywhere, who are out to destroy the uity and fraternity of our country. We have been opposing them in Assam; we have been opposing them in Punjab. But if you want to try to fight the extremists,, you have to accede to the genuine demands of the people so that the extremists are isolated. Unfortunately, I must say that the Akali leaders, because of extremism, could not follow their line consistently. I also agree with Mr. Vajpayee that the Central Gov? ernment wanted to take certain advantage of the extremists. This should not have been done. In Tripura, they joined hands with the extremists. This sort of attitude taken by the Central Government is not helping the unification of the emotions of the people of India. So, I think, even at this late stage, wisdom will dawn on the ruling party and they will sit round the table, because the differences have been narrowed down and this can be amicably settled.

श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार : (फरीदकोट) : स्पीकर साहब, मेरे आनरेबल कुलीग श्री वाजपेयी जी ने जो 5 नवम्बर 1982 को पंजाब की सिचुएशन के बारे में इस हाउस में प्रस्ताव पेश किया, उस पर आज बहस हो रही है, फर्दर डिस्कशन हो रही है । उस वक्त उन्होंने चन्द अलफाज ही बोले थे ।

आप सब को पता ही है कि उस वक्त की सिचुएशन आज से अलग थी । अकालियों की कुछ मांगें प्रधान मंत्री ने मान ली हैं । अब रावी-व्यास वाटर और टैरेटरी के मसले हैं । 1955 की ट्रीटी के बारे में जो इन्होंने कहा है, मेरे ख्याल में ये उसको छोड़ना नहीं चाहते, यह अकालियों की गलत डिमांड है कन्फ्रन्टेशन के बजाय बैठकर बातचीत के जरीये सब बातें हो सकती हैं । मुझे बड़ी खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने, हिन्दुस्तान की सरकार ने तमाम अपोजीशन मेम्बर्स को भी कांफिडेन्स में लिया और उनकी बातें सुनीं और जैसा वाजपेयी जी ने कुछ बताया, काफी मसले हल हुए । अब मैं एक सवाल करना चाहती हूं । वाजपेयी जी, 1966 में शाह कमीशन के सामने जो मेमोरेण्डम पेश किया गया वह पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया था और उस पर सभी पार्टियों के दस्तख्त हैं, सिवाय एक अकाली पार्टी के । हमारे हंसराज शर्मा जी उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे, अब भी शाह कमीशन की जो किताब छपी है, उसमें वह मेमोरेण्डम है । फाजिल्का और अबोहर का सवाल ही पैदा नहीं होता था, बल्कि उन्होंने तो कहा कि कालका भी हमें मिलना चाहिए और गूला भी हमें मिलना चाहिए । इसके अलावा जो भी पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं वह हमें मिलने चाहिए । मैं इस बात पर पूरी तरह से यकीन करती हूं कि जो भी बाकी टैरिटोरियल मसले होंगे वह भाषा के आधार पर होने चाहिए, किसी कास्ट, धर्म या मजहब के आधार पर नहीं होने चाहिए ।

अब एक बात मुझे बताइये । 1977 में आपको एक बड़ा अच्छा मौका मिला था । 1977 से लेकर 1980 तक । उस वक्त वाजपेयी जी फारेन मिनिस्टर थे । जनता पार्टी का यहां राज था और अकालियों का पंजाब में राज था लेकिन उस वक्त कोई मसला नहीं उठाया गया । उस वक्त आप भी कुछ काम करते । अब रिलिजस डिमाण्ड मानी गई है, बाकी भी मानी जायेंगी, सभी से मिलकर और बात करने के बाद। आपको याद होगा कि कब से कहा गया है कि चण्डीगढ़ पंजाब में जायेगा---चण्डीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए, इसके बारे में कोई शक नहीं है । उस वक्त भी कहा गया था लेकिन इतने साल गुजर गए, इस बात को किसी ने उठाया ही नहीं । आप बुरा न मानें वाजपेयी जी, एलेक्शन तो आप अकालियों से मिलकर इकट्ठा लड़ लेते हैं, सरकार भी पंजाब में बना लेते हैं और अब ख्वामखाह गरीब लोगों को क्यों लड़ाते हैं ? लेकिन अभी लास्ट में आपने जो अपील की है उससे मुझे बड़ी खुशी हुई है । (व्यवधान) अकाली जो हैं वह तो लीडर नहीं हैं सिखों के, सिख कांग्रेस में भी हैं, सी पी एम में भी हैं और अब तो वाजपेयी जी ने भी सिखों को अपनी जमात में ले लिया है । यहां पर जब खालिस्तान के बारे में बहस हुई थी तो मैंने यह बात कही थी कि हिन्दू फेमिली का जो बड़ा लड़का होता था वह सिख बनता था । अब मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती क्योंकि आज हिस्ट्री का दिन नहीं है । लेकिन जैसा कि स्पीकर साहब ने यहां पर बताया है कि सिख गुरू हिन्दुस्तान के कोने-कोने में गए हैं और उनके वहां पर गुरूद्वारे हैं । हिन्दुस्तान छोडकर वे मक्का मदीना भी जाकर आए हैं । जैसा कि गुरू नानक जी को आपने कोट किया, उन्होंने कहा है अव्वल अल्ला नूर पाया, कुदरत दे सब बन्दे । एक नूर दे सब जग उपजा, कौन भले कौन बन्दे । फिर क्यों लड़कर खून बहा रहे हैं ?

जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ इन्टरनेशनल बार्डर लगता है, पंजाब एक बड़ी इम्पार्टैन्ट स्टेट है और यह केवल अकालियों का मसला नहीं है । पानी का मसला हर पंजाबी का है---ख्वाह वह हिन्दू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो या किसी भी जात का हो । स्पीकर साहब, आपकी जमीनों को भी पानी चाहिए । दाढ़ी केश न

[श्रीमती गुरबिंदर कौर बराड़]

हुआ तो क्या हुआ, पंजाबी तो हैं । हम इस बात को कन्डेम करते हैं कि डा. जगजीत सिंह ने बड़ा खतरनाक मसला उठाया और हम उसके साथ हैं, बिल्कुल सहमत हैं । इसके साथ मेरी अपील है कि हर सिख को यह न समझा जाए कि वह खालिस्तान की डिमांड करता है । यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेशनलिस्ट पूरे हैं, पूरी कुर्बानियां दी हैं, कभी पीछे नहीं हटे हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए । प्रधान मंत्री जी को माइनोरिटीज का बहुत ही ख्याल है । यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि नेहरू खानदान ने माइनोरिटीज की रक्षा की है और प्रधान मंत्री जी के नीचे सब मसले हल हो सकते हैं । इसलिए हमको चाहिए कि हम सब बैठकर, कन्फ्रन्टेशन के बजाय थ्रू-नैगोसिएशन्स बात करें । यह मेरी आप से प्रार्थना है।

पंजाब से 13 सदस्य हम चुन कर आए हैं। 12 तो हम हैं और एक अकाली है, जिनकी शकल आपने शायद कभी देखी होगी ।

एक माननीय सदस्य: वाजपेयी जी दूसरे हैं ।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर बराड़: 117 सदस्य विधान सभा में हैं । 37 उनमें से अकाली हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम पंजाब के रक्षक हैं और बाकी सब लोग ऐसे हैं। हम सब मिल कर बैठें और मिल बैठकर इस मसले को हल करें--जैसी कि मैंने आपसे अपील की है । यूनिटी के साथ बैठें तो सारे मसले हल हो जायेंगे । होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं । यह जल्दी मसला ज्यादा डिले नहीं होने देना चाहिए । इसको जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए, ताकि पंजाब डवेलप हो, पंजाब और आगे तरक्की करे । पंजाब के लोग हर मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं । हिन्दुस्तान एक रहेगा, हिन्दुस्तान के टुकड़े नहीं किए जायेंगे और पंजाब में हिन्दू एकता कायम रहेगी ।

स्वामी इन्द्रवेश (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, पंजाब के मसले के साथ हरियाणा का मसला भी जुड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय: दोनों जुड़वां हैं ।

स्वामी इन्द्रवेश: पिछले कई सालों से राजस्थान का भी जुड़ा हुआ है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल): हिमाचल वालों को पता ही नहीं है, जहां से पानी निकलता है ।

अध्यक्ष महोदय: विशाल हृदय है ।

स्वामी इन्द्रवेश: पिछले सालों में जो पंजाब की हालत रही है, उसका दंड सारा हरियाणा को भी भोगना पड़ रहा है। 1955 में रावी-व्यास के पानी के लिए 110 करोड़ रुप्या देकर पाकिस्तान को, हरियाणा उस समय पंजाब में था, पानी खरीदा गया था । पंजाब में जमीन के नीचे मीठा पानी है, नहरें और दरियायें हैं । यह हिस्सा जो हरियाणा का कहलाता है, वहां जमीन के नीचे ज्यादा पानी भी है, बंजर है । यह सारा पानी हरियाणा के लिए खरीदा गया था । 1955 में जो फैसला हुआ था, उसके मुताबिक पंजाब को 7.20 ए.एम.एफ., राजस्थान को 8 ए.एम.एफ. और जम्मू और काश्मीर को 0.65 ए.एम.एफ. लेकिन 1976 के फैसले के अनुसार हरियाणा और पंजाब को आधा-आधा पानी देने का फैसला हुआ था । 1981 में जो फैसला हुआ, उसमें पंजाब का पानी बढ़ गया, राजस्थान का भी बढ़ गया और हरियाणा के साथ यह पाबन्दी लगा दी गयी कि पानी ज्यादा नहीं दिया जाएगा । इस के साथ साथ हरियाणा में सैंकड़ों करोड़ रुपये लगा कर नहरें बनाई गईं । यह पानी पंजाब के खेतों से हो कर आना है, लेकिन पंजाब में चाहे अकालियों की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इस मुद्दे पर दोनों एक लाइन पर खड़े हैं । सतलुज-यमुना नहर खोदने नहीं दे रहे हैं । यह सरकार की जिम्मेदारी है, दो सालों का सरकार ने वचन दिया था, डेढ़ साल बीत गये हैं अभी तक कोई कार्य उस पर नहीं हुआ है । अब यह तो सम्भव नहीं है कि हरियाणा के लोग शस्त्र ले कर पंजाब में नहर खोदने जायेंगे । यह तो आप की जिम्मेदारी है कि हरियाणा की धरती जो बिना पानी के बंजर पड़ी हुई है उसके हिस्से का सारा पानी उस को मिले। यह

1976 का फैसला था. आज 7 साल हो गये, इस तरह से सारा फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है । सरकार कुछ लोगों के आन्दोलन को देख कर यह महसूस करने लगती है कि पंजाब में पता नहीं क्या हो जायेगा । मैं यह समझता हूं– सरकार की इस ढीली नीति के कारण सारे देश के ऊपर साम्प्रदायिक असर पड़ रहा है ।

जहां तक भाषाई समस्याओं की बात है, क्षेत्रीय समस्या की बात है, अभी जैसा हमारे एक साथी ने कहा—हमें इस में कोई आपत्ति नहीं है कि चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए । मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों दे दिया जाये? शाह कमीशन ने चण्डीगढ़ हरियाणा को दिया था। जिस आधार के ऊपर हरियाणा और पंजाब का बटवारा हुआ, खरड़ तहसील हरियाणा को दी गई, चण्डीगढ़ हरियाणा को दिया गया, लेकिन आज हर एक आदमी यह समझने लगा है कि चण्डीगढ़ तो पंजाब को देना चाहिए, लेकिन फाजिल्का और अबोहर की चर्चा अभी नहीं करनी चाहिए । यह कैसी विडम्बना है? यदि तलवार दिखा कर फैसले होंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस पर फैसले होंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि सरकार लोगों को प्रेरित कर रही है कि लोग हिंसा के रास्ते पर चलें, लोग तलवार ले कर मैदान में आयें, रास्ता ले कर झगड़ा करें, उस के बाद सरकार घुटने टेक देगी और वैसा ही समझौता हो जायगा ।

यह जो क्षेत्र का मामला है, इस में हरियाणा के साथ सदा अन्याय हुआ है । भाषा के आधार पर दोनों प्रदेश बने । पंजाबी बोलने वाले लोग पंजाब में और हिन्दी बोलने वाले लोग हरियाणा में गये । लेकिन जो कुछ वहां पर हुआ, अब उस की जानकारी मैं आप को देना चाहता हूं । फाजिल्का और अबोहर के बारे में जो आज यह कहा जा रहा है कि उस के बारे में तो अभी आयोग बैठाना चाहिये, उस के बारे में फैसला किया जाना चाहिये—तीन बार उस समय के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों ने कुछ गांवों को निकाल कर, मेरा तात्पर्य है फाजिल्का से निकाल कर, मुक्तसर तहसील में डाला । उस में एक गांव केन्दुखेड़ा को इस लिये निकाला गया कि हरियाणा के साथ फाजिल्का-अबोहर का सम्पर्क टूट जाय और ये दोनों इलाके पंजाब में रह जायं । जिस समय 1970 में देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने अपना एवार्ड दिया, उस समय यह केन्दूखेड़ा गांव भी साथ में देना पड़ा । इस तरह से यह सारा षडयन्त्र किया गया, हरियाणा से इन इलाकों को काटने के लिये और देश के सामने यह नक्शा पेश किया जा रहा है कि फाजिल्का और अबोहर भी वहां जाने चाहिये । यह हालत आज बनी हुई है । वहां पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं भाषा के आधार पर उन के सामने बड़ी परेशानी पैदा हो गई है, वे हरियाणा या राजस्थान के गंगानगर में जा कर पढ़ते हैं और हिन्दी पढ़ने के लिए वहां पर कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है। उन की बोली हिन्दी है, भाषा हिन्दी है ।

केवल फाजिल्का और अबोहर को काटने का ही षडयन्त्र नहीं किया गया, बल्कि यह जो भाखड़ा बांध है, यह भाखड़ा बांध पहले कांगड़ा जिले में होता था, उस को होशियारपुर जिले में डाल कर पंजाबी भाषी जिले में डाल दिया । ये जो लालडू, डेराबासी 40 गांव कलोसिया स्टेट में होते थे और जिनकी छिछोली कैपीटल थी, उन 40 गांवों को हटा कर पटियाला में मिला दिया जिससे कि हरियाणा का सम्पर्क चण्डीगढ़ से टूट जाए । यह जो षडयन्त्र किया जाता रहा है, इस पर कोई सोचने को तैयार नहीं है, इसके इतिहास में जाने को कोई तैयार नहीं है कि यह षड्यन्त्र क्यों हुआ । या तो ईमानदारी से आप भाषा के आधार पर जो प्रदेश बनाये गये हैं, उस आधार को मान कर चलें या किसी सर्वमान्य आधार को मान कर चलें । इस आधार के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है, इस आधार को क्यों नहीं माना जा रहा है, यह मेरी समझ में नही आता ।

मैं समझता हूं कि यह जो राजनीतिक फैसला होने की चर्चा चल रही है, उसके लिए सब से पहले यह जरूरी है कि हरियाणा के लिए पानी लाने के लिए जो नहर बनायी जा रही है, उस नहर को जल्दी से खुदवाना चाहिए । अगर आप इस नहर के काम को इसी ढंग से लटकाये चलते रहे तो हरियाणा को जो पानी मिलने वाला है वह फिजूल में पाकिस्तान को जाता रहेगा । उस पानी

[स्वामी इन्द्रवेश]

को पंजाब को जरूरत नहीं है । उसके बाद भी वह पानी हरियाणा को नहीं मिल रहा है । इस नहर को शीघ्र बनाया जाए, बेकार इसको लेट किया जा रहा है । इससे सारा हरियाणा प्रदेश प्रभावित हो रहा है । इन सारी बातों को देखते हुए ही इस विषय पर विचार करें । केवल पंजाब को या कुछ लोगों के आन्दोलन को देख कर ही कोई फैसला नहीं लेना चाहिए । परन्तु जो यथार्थ है, वस्तुस्थिति है, जो लोगों का वास्तव में अधिकार है, उसके मुताबिक आपको फैसला लेना चाहिए ।

हमारी प्रधान मंत्री ने अभी एलान किया है कि हमने उनकी धार्मिक मांगों को स्वीकार कर लिया है। अब इस देश में यह बड़ी विडम्बना है, बदकिस्मती है कि धर्म के मामले में कोई परिभाषा देश के सामने नहीं है आखिर आप धर्म किस को मानेंगे? एक आदमी कहे कि मैं तलवार ले कर चलूंगा और यह लेकर चलना मेरा धर्म है तो आप उसको धर्म मान कर चलेंगे । मैं आप से पूछना चाहता हूं कि अगर कल को दो लाख आदमी यह फैसला कर लें कि हम पिस्तौल ले कर चलेंगे, यह हमारा धर्म है तो क्या आप पिस्तौल लेकर चलने की अनुमति दे देंगे ? क्योंकि नहीं तो उनके धर्म को खतरा पैदा हो जाएगा । अगर इस तरह की मांगों के आगे सरकार फैसला करने को तैयार हो जाए, झुकने को तैयार हो जाए तो इस देश में कभी भी कानून का शासन कैसे चलेगा ।

आज पंजाब में क्या हालत है ? पंजाब में दिनदहाड़े निरपराध लोगों पर गोली चला कर लोग धर्म स्थानों में जाकर छिप जाते हैं । पंजाब में आज दो कानून चल रहे हैं--एक देश का कानून और दूसरा गुरद्वारे का कानून चल रहा है । अगर सरकार इसी ढंग से शासन चलाना चाहती है तो बात दूसरी है ।

मैं यह नहीं समझता कि कोई भी सिख मानसिक रूप से गौ का कत्ल करने का साहस करेगा । लेकिन लोग षड्यंत्र करते हैं और इस तरह से साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़का कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं । मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि इस समस्या को जितना लटकाया जाएगा, वह उतनी ही लम्बी और विकट होती जाएगी । पानी के मसले पर भाषा के मसले पर आपका ध्यान जाना चाहिए और हरियाणा के साथ आपको न्याय करना चाहिए ।

श्री जी. एस. निहालसिंहवाला (संगरूर): स्पीकर साहब, वाजपेयी जी ने आज यहां पंजाब का मसला उठाया । कई बातें उन्होंने बिल्कुल ठीक कहीं । स्वामी जी को मैंने सुना । मैं उनकी कई बातों से इत्तिफाक करता हूं ।

स्पीकर साहब, आज हमारी हालत ऐसी बनी हुई है जो कि हम बयान नहीं कर सकते । इस मुल्क में जम्हूरियत है । जम्हूरियत में किस तरह से चलते हैं, किस लोगों को नुमाइन्दगी मिलती है, किसी मसले पर कैसे फैसला किया जाता है, यह पंजाब में बिल्कुल उल्टा है । पंजाब से आये पार्लियामेंट के 13 मेम्बरों में से 8 सीटों पर सिखों की डोमिनेशन है । उन आठ में से भी, मालवा से, जहां से अकाली नेता क्लेम करते हैं, पटियाला, भटिंडा, संगरूर, फरीदकोट, फिरोजपुर, लुधियाना, ये मालवा के जितने इलाके हैं, वहां से कोई आदमी इनका रिटर्न नहीं हुआ । अमृतसर से एक तुड़साहब सिक्खों के वोट लेकर आए हैं। यहां सिक्खों का डामीनेशन है । पंजाब की असेंबली में 117 सीटें हैं और इन 117 सीटों में से 37 अकालियों के पास हैं । इसमें रिजर्व सीट्स भी हैं । कुछ शहरों से भी वोट मिले हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ये ताकत में नहीं रहे तब इन्होंने सिक्खों के नाम का नारा लगा दिया। सिक्ख क्या चाहते हैं, सिक्ख किनके पीछे हैं, इस चीज को ये लोग नहीं देखते । पंजाब के लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, असेंब्ली में भी और पार्लियामेंट में भी । जब सरकार नहीं बना पाए तो मोर्चा लगा दिया । हम खामोश बैठे रहे । न हमको सेंटर पूछता है, न स्टेट पूछती है, पार्लियामेंट के मेम्बर हम जरूर हैं । आज भी वाजपेयी जी की मेहरबानी से बोलने का मौका मिल गया है नहीं तो हम जुर्रत भी

नहीं करते बोलने की, इसलिए कि शायद हमको सजा मिले कि क्यों आप इस झंझट में पड़ते हैं। क्यों आपने यह मसला उठाया, इसलिए खामोश बैठे रहे।

दो तरह की इनकी मांगे हैं–एक तो धार्मिक और दूसरी पालिटिकल। धार्मिक मांगे तो तकरीबन मान ली गई हैं, सिर्फ एक मांग पूरी नहीं की गई कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी आल इन्डिया बेसिस पर हो। हमारे अध्यक्ष महोदय भी पंजाब के हैं। कुछ जासड़ भी सिक्ख हैं, इनके बड़े करीबी हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमारा खानदान है, करीबी क्यों कहते हैं।

श्री जी. एस. निहालसिंहवाला : इन्होंने दिल्ली के सिक्खों को कहा कि आप दिल्ली के चुनावों का बायकाट करिए। लेकिन दिल्ली के सिक्खों ने अपनी मर्जी की––इनका हुकम नहीं माना। हुजर साहब नांदेड़ के सिक्ख इनका कहना मानने को तैयार नहीं हैं, पटना साहब के सिक्ख इनका कहना मानने को तैयार नहीं हैं। पंजाब में जितनी आबादी सिक्खों की है, उतनी ही आबादी बाकी हिन्दुस्तान में सिक्खों की है। वे इनका कहना नहीं मानना चाहते। वे कहते हैं कि हम धर्म को अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं। इनको सिक्ख गुरुद्धारा एक्ट आल इंडिया बेसिस पर बनाने का क्या हक है? इनका मतलब यह है कि वहां के सिक्ख पूंजी जमा करके और अमृतसर लाकर टौंडा साहब को दें और ये खाएं। अजीब तमाशा है।

इसलिए मेरा कहना है कि यह सिक्खों का मसला है और मैं भी सिक्ख हूं, नेशनलिस्ट हूं, पक्का सिक्ख हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): कुछ कच्चे भी हैं।

श्री जी. एस. निहालसिंहवाला: हां हैं, कुछ कच्चे भी हैं। आप प्राइवेट तौर पर पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कच्चे और पक्के सिक्ख में क्या फर्क होता है।

तो मेरा कहना यह है कि अगर आल इंडिया बेसिस पर करना है तो सारे हिन्दुस्तान के सिक्खों की इसमें राय लेनी होगी और देखना होगा कि मेजारिटी चाहती है या नहीं।

दूसरा पालिटिकल सवाल है। सबसे बड़ा पानी का सवाल है। पानी के मसले में आम जमींदार को इन्होंने गुमराह किया है। आप और मैं एक ही इलाके के रहने वाले हैं। मैं जानता हूं कि कहां-कहां मीठा पानी है और कहां नहीं है, जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा। जो बैरानी इलाके हैं वहां मीठा पानी नहीं है। चौधरी साहब के इलाके अबोहर में मीठा पानी नहीं है, फाजिल्का, मुक्तसर, फरीदकोट में नहीं है। भटिंडा सबसे बिरानी इलाका है, वहां मीठा पानी नहीं है। तो इस पानी के मसले में हम यह बिल्कुल कहने को तैयार नहीं हैं कि आप किसी का हिस्सा हमको दे दो। जो कायदे-कानून के मुताबिक हमारा हक बनता है वह हमको दिया जाए।

मैं दावे से कहने के लिए तैयार हूं कि पंजाब ने ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल किया है जो अपने हक का था यानी 4.61.6261, इसलिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि मौजूदा सिस्टम को बाद डिस्टर्ब न किया जाए। जो सरप्लस वाटर राजस्थान और हरियाणा का बनता है, वह हिसाब से उनको दे देना चाहिए। मगर मुनसिफाना तौर पर, रियायत नहीं होनी चाहिए, न हमारे साथ और न किसी के साथ।

तीसरी बात रही टैरिटोरियल के बारे में। मैं दावे से कहने के लिए तैयार हूं, यहां नहीं बाहर भी, सड़क पर भी और स्टेज पर भी कहता रहा हूं कि जितना अकालियों ने सिखों का और पंजाब का नुकसान किया और कोई नहीं कर सकता। पंजाबी पलवल और कुल्लू-मनाली तक पढ़ाई जाती थी। सिर्फ इसलिए इन्होंने यह जुल्म किया कि हमारी सिख डोमिनेटेड सीटें कितनी आयेंगी, जिनसे हमारी सरकार बने उतनी ले लो। मुझे इल्म है. जिस दिन अबोहर और फाजिल्का का बदकिस्मती से ऐलान हुआ था, मैं उस वक्त भी पार्लियामेन्ट में था और मुझे वर्किंग कमेटी में वहां बुलाया गया था। उस दिन

[श्री जी. एस. निहालसिंहवाला]

उन्होंने सोचा था कि सन्त जी ने मर जाना है, सड़कर जल जाना है, कुन्ड बना लिया और मिट्टी का तेल डाल दिया जिससे छलांग न मार जाए। सरदार हुकम सिंह हुकमनामा लेकर कल आते हैं और सन्त जी को बचाएं तो कहेंगे फाजिल्का दे दो, यह उस वक्त किया। उस वक्त कमजोरी का फायदा उठाया था। उनमें यह बचाने की कमजोरी आ गई चूंकि वह मुनसिफाना फैसला नहीं था। वह इम्पलीमेन्ट नहीं हुआ, फाजिल्के, चण्डीगढ़ और अबोहर कुछ नहीं मिला। मैं आपका ज्यादा टाईम नहीं लूंगा। जहां भी पंजाबी स्पीकिंग कंटीग्यूअस है, चाहे वह रोढ़ी का इलाका है, चाहे फाजिल्का के गांव हैं, चाहे भटिन्डा या सरसा के पास इलाका लगता है इसलिए मैं कहता हूं सरकार को दिलेरी से कर देना चाहिए। जो उधर गस्ती से चले गए हैं, सन्त जी की बचाने की कमजोरी के वक्त, उनको इधर दे दें और जो इधर रह गए हैं--उधर दे दें। ऐसा फैसला मुनसिफाना तौर पर होना चाहिए। मैं समझता हूं हमको तो सिख नहीं मानते। उनके यहां आठ एम. पीज हैं और मैजारिटी कांग्रेस में बैठी है। सिर्फ 4-5 आदमियों को मानते हैं, उनको नहीं मानते हैं। बदकिस्मती से ये सारे लीडर मेरे हल्के के हैं। तलवंडी और लोंगोवाल दोनों मेरे हल्के के हैं। सुरजीत सिंह बरनाला मेरे से हारे हैं, इसलिए वे भी हैं ही। सारे लीडर वहां के हैं लेकिन मैं छूट गया, क्या मैं सिख नहीं ? वहां जाटों की 80 परसेंट वोट है। वहां के लिए कांग्रेस ने कहा था कि यह तो सिखों का हल्का है इसको छोड़ दो, काटकर फिरोजपुर का, लुधियाना का वर्स्ट डोमिनेशन और कुछ संगरूर का हिस्सा डाल दिया और कहा कि एक सीट जाने दो। वहां भी सिखों ने इनको नहीं अपनाया। यहां पर ये चैम्पियन बने बैठे हैं कि हम सिख हैं। उन्होंने तो सन् 85 का इलैक्शन देखना है तब तक जंग जारी रखनी है। अगर जंग चलती रही तो वोट मिलेगी। (व्यवधान)

आज सरदार दरबारा सिंह को रिटायर कर दो, उनकी जगह तोहरा या तलवंडी को बना दो। कोई झगड़े की बात नहीं लेकिन मामला ठप्प हो जाएगा। मैं वाजपेयी जी से दरख्वास्त करूंगा कि यह बीमारी आपने ही उनको लगाई है। वे अकेले राज नहीं कर सकते थे, न कभी सोच सकते थे। अब मुश्किल यह है कि उन्होंने थोड़े दिन राज करके देख लिया। अब चिंता रहती है जब तक राज नहीं मिलता। इसलिए किसी नेशनलिस्ट पार्टी के साथ समझौता कर लिया करो। यह रोज जलने और मरने वालों के साथ न किया करो। मैं केन्द्र सरकार से दर्खास्त करूंगा कि जल्दी से जल्दी मुनासिब और मुन्सिफाना तौर पर जो पंजाब और किसी और सूबे के हक बनते हैं उनका युनीलेटरल फैसला कर दो और वह सब सिखों को स्वीकार है।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि जितने वक्ता यहां बोले हैं उन्होंने महत्वपूर्ण और बुनियादी चीजें सामने रखी हैं कि जो कुछ फैसला हमें करना है किसी भी रीजन के मुताल्लिक तो हम इंडियन फर्स्ट और इंडियन लास्ट हैं इस भावना को सामने रख कर करना है। यह बड़ी अजीब चीज है, और जब हमारी स्टेट्स बहुत ज्यादा हों और मुल्क में कुछ बटवारे, झगड़े, टंटा या फसाद हो तो हमें यही राष्ट्रीय भावना रख कर काम करना चाहिए कि हिन्दुस्तान हमारा है जिसके लिये हम सब गौरव करते हैं, उसके विधान की रक्षा के लिए शपथ ली है उसकी चारदीवारी के अन्दर रह कर ज-जो रीजनल प्रोबलम्स उठती हैं उनको हमें सुलझाना और सम्हालना है।

हमारा मुल्क एक सब कान्टोनेन्ट साइज का है और कभी कभी सब-कान्टीनेंटल डाइमेंशन की प्रोबलम्स भी खड़ी होती हैं। लेकिन यह जो हमारा बुनियादी उसूल है, यह जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबक हमने सीखा है, आजादी की लड़ाई के समय श्री जवाहर लाल नेहरू और मौलाना आजाद के आधीन कि हमारे देश में अलग अलग मजहब और भाषा रहेगी फिर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनाये रखेंगे इस बात को हमें हमेशा अपने जहन में रखना है और उसी के मुताबिक काम करना है। एक शायर ने कहा है :

गुलहाय रंग रंग के हैं रौनके चमन,
अय जौक इस जहां को है जेब इख्तलाफ से।

तो हिन्दुस्तान की ताकत या तरह तरह के रंगों के जो हमारे गुल हैं यह देश की रौनक बढ़ाते हैं ।

पंजाब का मसला जिनके बारे में सारा सदन और देश चिन्तित है उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो:

Punjab occupies a very pivotal and strategic position in India.

हिन्दुस्तान में पंजाब पर सारे देश को गौरव है । वतन परस्ती में कभी सिख पीछे नहीं रहे, बहादुरी और कुर्बानी में देश की आजादी की लड़ाई में सिख पीछे नहीं रहे । इस बात का फख्र सारे देश की जनता को है ।

जब यह डिमान्ड्स उठीं और उनके बारे में जब फैसला करना होता है तो मेरी शिकायत यह है कि हमारी सरकार ने डैक्सटैरिटी और डिलिजैंस क्या चीज है इसको नहीं सीखा । बहुत देर के बाद सोचती है । जब यह डिमान्ड उठी और डाइलेटरी टैक्टिक्स सरकार ने नहीं अपनाई होती तो मेरा ख्याल है कि यह मामला इतना नहीं बिगड़ता । अभी प्रधान मंत्री ने कहा कि सिखों की रिलीजस डिमान्डस मन्जूर करते हैं । तो जब डिमान्ड उठी रिलीजस, टैरीटोरियल और कुछ रावी, ब्यास के पानी की और कुछ पोलिटिकल डिमान्डस, तो इनके लिये सर-पहले से ही दूसरी पार्टियों से सलाह मश्विरा कर के एक नेशनल कंसेन्सस तैयार करती तो मामला इतना नहीं बिगडता ।

1500 hrs.

लेकिन जैसा मैंने कहा कि रिलीजस आफ डैक्सैटरिटी क्या चीज है, वह हमारी गवर्नमैंट समझती नहीं है । जब मामला बहुत बिगड़ जाता है, उसके बाद गवर्नमैंट खुद आती है ।

शुरू में जब यह चीज उठी तो हमने कहा कि यह अकालियों की डिमांड है, वह सिसैशनिस्ट है । उनको गवर्नमैंट ने कंडम करने का काम शुरू किया । गवर्नमेंट ने उनको सिसैशनिस्ट, ट्रेटर और एंटी-नेशनल वगैरह सब चीजें कह दीं और उसके बाद जब देखा कि गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है तो फिर कहा कि अपोजिशन वाले सब मिलकर चलो । हम ट्रीपारटाइट कमेटी में बैठे । वहां गवर्नमैंट ने देखा कि अपोजिशन ने कन्स्ट्रक्टिव रोल लिया है । जब इस तरह के प्राबलम होते हैं तो नेशनलिस्ट, नेशनलिज्म, वतन-परस्ती की दृष्टि से देखे जाते हैं । उस वक्त कभी भी पार्टीबाजी की बुनियाद पर नहीं चलना चाहिये । मुझे कहते हुए दुःख होता है कि शुरु में कांग्रेस पार्टी सब चीजों में पूरे-पूरे लड्डू खुद खाना चाहती है । आखिर में जब कांग्रेस के बसकी बात नहीं रहती है, मामला बहुत बिगड़ जाता है तो बाद में कहती है कि और लोग भी आयें और रास्ता दिखायें । यह एक जबर्दस्त चीज है ।

आने वाले दिनों में भी ऐसी बहुतसी चीजें देश में उठेंगी, उस समय गवर्नमैंट को चाहिये कि सब को साथ में लेकर नेशनल कन्सैन्सस खड़ा करने की कोशिश करे और वह एक कन्स्ट्रक्टिव एप्रोच होगी । अगर पहले गवर्नमैंट ने कंस्ट्रक्टिव एप्रोच की होती तो यह मामला इस हद तक बिड़ता नहीं ।

जो इनकी रिलीजस डिमांड्ज गवर्नमैंट ने मान ली है, यह बहुत अच्छी चीज है, मैं मानता हूं कि हैल्दी ट्रैड्ज आफ डैवलप्ड, अकालियों ने अपनी डिमांड को टर्न-डाउन किया है, यह कहा है कि हम देश की यूनिट को भंग करना नहीं चाहते हैं । अभी एक रैज्यूलूशन उन्होंने पास किया है, मैं उसके लिये उनकी सराहना करूंगा, उनको मुबारिकबाद दूंगा । गवर्नमैंट ने भी जो रोल अपनाया है, अभी भी जो उनकी मांगें हैं, उनके बारे में अपोजिशन को साथ लेकर नेशनल कन्सैंसस खड़ा करने का तरीका जो गवर्नमैंट का है, मैं उसकी भी सराहना करूंगा और कहूंगा कि यह अप्रोच हमें जारी रखनी चाहिये । यह अप्रोच रखकर यदि हम चलेंगे तो यह काम काम ठीक हो सकते हैं । हम इस चीज का फैसला करें कि उनकी डिमांड्ज में दो तीन चीज जो हैं उनके बारे में हमारी एप्रोच साफ होनी चाहिये ।

एक तो गवर्नमैंट को यह करना चाहिये कि जितने डिस्पयूटस हैं, वह थ्रू नैगोसियेशन करेंगे, हम किसी के कंडैमनेशन के

[श्री रतन सिंह राजदा]

अधिकारी नहीं हैं । किसी को कंडम कर के, किसी को बुरा-भला कर के नहीं, बल्कि हम उनके साथ बैठने की बात करें । मैं एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं करता, उसकी सराहना हम नहीं कर सकते, वायोलैंस की सराहना नहीं कर सकते, लेकिन नैगोसियेशन सब सवालों के लिये हो सकती है । मैं चाहूंगा कि यह अकालियों के लिये भी लाजमी है, गवर्नमैंट और दूसरे सब लोगों के लिये लाजमी है कि नैगोसियेशन से एक टेबल पर साथ-साथ बैठकर मसलों का फैसला करें ।

ट्रीपारटाइट टाक्स जो हमारी चलीं जो सलाह-मशविरा हुई, उसमें जो इश्यूज बाहर आये हैं, उसमें आपने देखा होगा कि हम सौल्यूशन के नजदीक आये हैं । सब पार्टियों वाले, गवर्नमेंट के लोग एक साथ टेबल पर बैठे थे तो हम सब--

We were nearer the solution; we are already nearer the solution.

मैं नहीं समझता कि किस लिये यह मामला बिगड़ना चाहिये । अभी तक यह तय हुआ था कि जितने वाटर डिसप्यूट, रावी-ब्यास के पानी के सवाल हैं, वह एक ट्रिब्यूनल को दिये जायें और वह ट्रिब्यूनल रिवर डिसप्यूट ट्रिब्यूनल एक्ट, 1956 के मुताबिक, उसके प्रावीजन के मुताबिक फैसला करे । जहां तक टैरिटोरियल डिस्पयूट का सवाल है और डिफरेन्सेज का सवाल है वह भी

That could be referred to a commission.

और वह कमीशन अपना फैसला दे ।

तीसरे जो स्टेट और सैंटर के रिलेशन की बात होती है, उसके बारे में

That could be examined by legal and constitutional experts.

वह कर के सैंटर और स्टेट रिलेशन के बारे में भी फैसला हो सकता है । अब अकालियों ने अपनी मांगें कांस्टीट्यूशन के प्रावीजन के अन्दर रखने को कहा है। उन्होंने अपना एक प्रस्ताव पास कर के कहा है --

We stand by the unity and integrity of the country.

उस पर भरोसा रखकर हमें आगे चलना चाहिये और इसी वातावरण व हवा को हमें ताकतवर बनाना चाहिये ।

मैं गवर्नमैंट को यह कहना चाहता हूं कि एक भी कदम हमें ऐसा नहीं उठाना चाहिये जिससे मामला और ज्यादा बिगड़े । जब सिख भाई एशियाई गेम्स के लिए दिल्ली की तरफ आ रहे थे उस वक्त भजन-लाल जी ने जो एलान किया और जिस तरीके से उन्होंने सिखों के साथ व्यवहार किया उस को मैं कन्डम करता हूं । बड़ी जिम्मेदारी और बड़े दुख के साथ मैं उसको कन्डेम करता हूं । जो लोग वायलेन्स करना चाहें उनके खिलाफ आप ऐक्शन ले सकते हैं लेकिन सारे सिटिजन्स को एक समान माना जाना चाहिए और उनमें आपस में कोई भेद नहीं होना चाहिए। आपने सिखों के सैंटिमेन्टस को धक्का पहुंचाया । ला एण्ड आर्डर के लिहाज से स्टेप्स न लेते हुए जो एलान किया गया और जिस तरह से पब्लिक को इंस्टीगेट करने की कोशिश की वह बहुत गलत बात थी ।

इन्हीं अलफाज के साथ मैं कहूंगा कि आज फिर से हमें दुनियां के चौराहे पर कहना है कि सिख और हम सभी हिन्दुस्तानी एक बहते पानी की तरह से हैं । बहता पानी काट सके, जग में देसी तलवार नहीं ।

we are Indians first and Indians last

हम अपने उसूलों पर चलेंगे और मैं इस बात को मानता हूं कि पंजाब का मसला हल करना कोई मुश्किल नहीं, आसान होगा।

Given goodwill, fairplay and some of justice, the solution will be in sight.

With these words, I have done.

MR. SPEAKER: Before I call the next member, I would like to take the consensus of the House. We have got about 25 minutes more. If the House so agrees, we can give 2-1|2 hours for the Private Members' Resolution after finishing this.

HON. MEMBER: Yes.

MR. SPEAKER: So, we shall carry on with this.

Prof. Ranga.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Mr. Speaker, Sir, I do not wish to speak today on behalf of the Congress: I do not want to speak as a party man. I speak as one of the founders of the Constitution.

I am glad my hon. friend who has just now spoken has taken the right stand that we are all Hindustani people; we are all Indians. We are bound by our Constitution. We would like to live together although professing different religions as sons and daughters of Bharat Mata. I would like to make an appeal to our friends from Punjab, the Sikhs, and I would like them to realise and say to themselves and be frank with themselves also, whether they would like to live there as Indians or merely as Sikhs: whether they would like to have Hindus also as their co-parteners in that area or whether they want to go the way, the wrong way, with so many of our friends had gone in Pakistan, in founding Pakistan.

I felt sure, when we were achieving freedom, that our Sikh friends wanted to be in India and not to have a separate home for themselves, keeping away everybody else as the Pakistanis had done. It was because of that we all agreed. When I was there with the Congress and later with the Swantantra Party also, we agreed with Master Tara Singh that there should be a separate Punjab State, not for Sikhs alone, not for Hindu alone, but for both the groups of people who are living together. Let our hon. friends, the Sikhs, also realise that Hindus are as devoted worshippers of their gurus as they themselves. They may wear turbans; they may keep beard and all the rest; they may carry their kirpans—that may be their special professions—but it does not mean that they should consider Hindus to be different from themselves in their devotion to their gurus.

We have gurus in other religions also. Lingayats have got their gurus. They have made a lot of sacrifices in virtue of their faith in Lord Shiva. So many things can be said about Vaishnavites and other people also. We have all got our gurus; we worship these gurus. Merely because we worship these gurus, it does not mean that we must turn our face against all other people who worship some other gurus.

I want our friends from Punjab also, our Sikh friends, to realise that they are not living in Punjab alone. They are very enterprising. They have gone to Ottawa and when some injustice is done to our Sikh friends, in Canada, our blood boils, our Government protests and Members of Parliament and the Government to protest through our own Embassy. They are there in Madras, in Cape Comorn, everywhere. They have benefited as a result of the tremendous economic and social development we have been making for the last 35 years. If any community is to be singled out as the best possible enterpreneurs and industrialists and beneficiaries, it is the Sikhs. The one single community which has made the single biggest possible contribution to the development of our country is Sikhs.

I would like these friends in Punjab to realise their responsibility towards all the Sikhs all over India and then to make their demands.

I have one confession to make. I, along with our constituional founders, have committed one big blunder and that was to have adopted the British parliamentary system in a blindfolded manner, party against party, my party at any cost, a kind of a new political religion, we started. The result is we are now suffering from what is known as one vote majority tyranny and it has led to these defections. Just now he has mentioned the name of a State where they took away six or seven votes from one side, quietly. How? No one knows. But anyhow he manufactured a majority. That majority

[Prof. N. G. Ranga]

was not there at the time of the election. And then immediately all these people began to raise *halla-gulla.*

I told you that in the whole of India it is not possible to have all-party Government. But in certain problem States, especially in Punjab and Meghalaya and in some other States also, we should have political residence statesmanship in adequate degree to be able to raise above our own party loyalties to be willing to share power with the other political parties so that all political groups would have some satisfaction of having a share in the power that is to be there in a particular State. If we were to make an experiment in that direction, we would be able to find better solution for problem-States like Punjab.

I congratulate the Opposition party leaders, a number of them, who came forward some months ago, to issue an appeal to our Sikh friends in Punjab not to go to extremes and, at the same time, to warn the country as a whole not to go on yielding all the time to the extremist possible demands that might be coming from any one religious community. I was very happy about it. I am also happy that all our friends agree to offer cooperation to Indiraji and to our Government.

But just because they happen to be in those parties on that side, and Indiraji and all of us happen to be on this side, it is not proper to go on accusing her party for anything and everything. What was the wrong thing that she has done? She wanted the country to recognise the sanctity of an agreement that was reached by three or four State Governments over river water distribution. Is she wrong in it? Is it the first time that she has offered to talk to them? Is it not a fact that it is those people who have simply refused to talk to the Government of India, to Indiraji, to everybody? Is it not a fact that it was those people who demanded that Indiraji should go and talk to them in their *takts?* We say that we are opposed to imperialism. But they talk about their takt and they want the Prime Minister of the whole of India to go there and to bow before them.

She was prepared to do even that. She has been patient, I should say, eternally patient. Some of the Opposition Party Members as well as their leaders also must have felt very unhappy as I had felt unhappy over the kind of—what did I call it—endless patience that she has exercised over all this. What was wrong in asking those people not to come with their *kirpans* and behind the kirpans with the bullet demand that was emanating from wherever that religious leader was at the time of the Asiad? Suppose the Government had not taken that action and suppose something had happened here what would have been the fate of India, what would have been the reputation of India the world over when the whole world was here at the Asiad? Therefore, merely because you happen to be on that side—I also happened to be on that side—it is not proper to go on finding fault with the Government for anything and everything. Today she has asked for cooperation from the Opposition. The day before yesterday she asked for cooperation from the Opposition over Assam. My hon. friend, Mr. Ravindra Varma charted out formula after formula in a patriotic manner and tried his best to cooperate with the Government. But all the Opposition was not united unfortunately. Some of the Opposition went the wrong way like my friend Mr. Vajpayee and we are faced with this terrible situation in Punjab as a result of this division among the Opposition themselves. But so far as Indiraji is concerned, let me tell you she has been suffering, she has been working under this impossible Parliamentary system where. . .

SHRI H. N. BAHUGUNA (Garhwal): You are saying this! A founding father of the Constitution is saying this!

PROF. N. G. RANGA . . .where she has got to keep away so many of these friends from the trammels of responsibility and yet carry on the adminis-

tration in the face of opposition, the kind of opposition that has been emanating from Punjab on the one side and from Assam on the other.

We all went to the people. I was defeated, and you were defeated, in 1971. In 1967 she came back here only with a minority and she was supported by the Communists and, therefore, she was able to run the government. We were there in the Opposition. Did I not offer my cooperation on behalf of my Party as well as myself to Indiraji in those days? I did. When our U.P. friends were also there in the Government and I was there in Rajya Sabha in the Opposition, did I not offer my cooperation to you, friends, whenever there were communal riots? A similar approach we must be prepared to make. At least in certain States especially in the north eastern tribal States, in Punjab and in some other States wherever you find the Congress coming out as the single largest party and at the same time not being able to form a Ministry, the Congress must be willing to invite the cooperation of other Parties and form a coalition,—What should I call that; would it be coalition? —an all-Party Government. Let us make an experiment. I made this suggestion when Pandit Jawaharlal Nehru was alive, and later, when Mr. Lal Bahadud Shastri was here, and again when Indiraji was there. They said: here as the Constitution and the mapority Party leader has got to be called to form the government. Afterwards, when Chaudhuri Charan Singh was called to form the Ministry, did he have the majority behind him? Yet, we did it and he was able to form a Ministry. If the leader of the single largest Party were to form the Ministry and invite the leaders of the Opposition Parties including Prof. Madhu Dandavate, our Communist friends and our BJP leader, where is the harm? They should be willing to work with it. But I am not prepared to make that suggestion here and now for the Government of India because I do not speak on behalf of the Government, on behalf of the Congress. It is for the Congress and all these Parties to put their heads together to think of some formula. So far as problem States are concerned, there must be, as far as it is possible, all-Party Government.

MR. SPEAKER: Please try to conclude.

PROF. N. G. RANGA: One minute more Sir. I have only placed my thoughts and suggestions before you. It is not going to be very practical because neither these friends nor those friends would agree to work on this basis. Therefore, what should we do in the meanwhile? I appeal to the Sikh friends in Punjab and Sikh friends all over India to stand by Indiraji, to stand by the Government as a whole and to stand by the Parliament and see that there is no division and no trouble whatsoever in Punjab. There are enemies on this side. There are enemies on that side, enemies in the two hemispheres who are only waiting for a chance. They were unhappy over what happened in Bengal. So they want similar misfortune to visit upon India. We should not give an opportunity to the inimical people in different areas in the world. So let us all work together even though we belong to different Parties and even though you find yourself on your side and we find ourselves on this side. Please don't be too much obsessed with power. I have never held any power. I am not a disappointed man. I am not a frustrated man. Therefore, I warn my friend, Mr. Vajpayee to exercise some patience with himself and with his party and see that his Party falls in line with the rest of us in Punjab as well as in Assam.

SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South): Now an all party government. That is the proposal before the House.

15.22 hrs.

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): Most of my predecessor speakers have pointed out to the serious necessity of settling the disputes in Punjab, particularly concerning the fact that it is a Border State as well as the continuance of the extremist activities there. Nobody has contradicted the fact

[Smt. Geeta Mukherjee]

that behind the extremists activity there are machinations of foreign powers as well. But everybody knows that in Punjab either among the Sikhs or among the Hindus all are not extremists. And this makes it very necessary to effectively intervene in isolating the extremists. For that quick settlement with the Akalis, in our opinion, is very necessary.

We were all very happy when we read in the newspapers that the talks are going to conclude successfully. But, unfortunately, it has not taken place, but that itself shows that there was some basis during the talks which, if pursued persistently, can settle the situation. With that end in view, we welcome the fact that some of the religious demands of the Akalis have been conceded by the Prime Minister. Now we think that the Prime Minister herself should take further initiative in having further talks. There should not be anything which stand on prestige. With this understanding I urge upon the party in power to take the initiative again.

In this about the demands that are outstanding I would like to mention a few things. About the Centre-State relationship question, I would appeal to the Akalis why it should be within the Anandpur Sahib resolution. It is a political question, it is not a religious question of the Sikhs. We, in various parts of the country, today feel strongly and it is the feeling of various Parties also, that this decentralisation of power and resources must be there. Therefore, they should not insist on anything which would prejudice in fact their case if they want more powers for the States and make a common cause. At the same time, I would urge upon the Centre to understand that the Centre-State relation question is very important and some initiative must be there from the part of the Centre to have a special discussion on this question with all political parties and all forces of the country who want better balance of Centre-State relations.

In respect of water dispute, in our opinion, the 1955 agreement should be adhered to but at the same time there are certain other things which should be definitely given to a tribunal without prejudice to 1955 agreement. Therefore, if the Prime Minister takes another initiative in that regard for re-referring to the tribunal without prejudicing 1955 agreement, I believe, that should help the situation because in the negotiations itself almost everybody agreed to it.

Mr. Deputy Speaker, Sir, about the territorial disputes our party is for giving Chandigarh to Punjab and at the same due territorial compensation and financial aid for the rest of the territorial question surely a mechanism can be found for resolving the same. It should not be on the basis of religion, as such, but other well known concepts on which disputes are settled in the world.

Sir, in order to help the Punjab situation one thing is very essential that all the secular democratic forces who claim themselves to be secular and democratic and all the political parties whether they are secular or not but claim themselves to be so, in the interest of the Punjab issue, it is very essential that their State unit's not only in Punjab but also in Haryana and Rajasthan speak in the same voice. But I am sorry to say that the ruling party's Punjab unit, Haryana unit and Rajasthan unit are not speaking in the same voice. This is the truth. They are arousing passions. This they should stop. BJP out-does the ruling party. It goes one step ahead. With all the intentions of making the Punjab situation more quiet this has to be taken into consideration that if they want peace then all these passion-arousing should be stopped. I would like to take pride about the fact that the Left Forces—including my party —have not only spoken in the same language in all the States but we have been trying in this situation to mobilise all the forces who would speak against extremists and secessionists and for bringing about secular atmosphere. I would like to congratulate the people of Punjab, Haryana and Rajasthan who despite the serious situation are trying to keep peace.

In this connection I would like to mention the fact that only of late there was an intellectual conference in Punjab which called itself 'Intelligentia for National Integration, Secularism, Punjab's Unity and Development' where a number of delegates assembled and they passed resolutions which said that:

"Separatist slogans and demands of Khalistan continue to be progagated in Punjab. The extremists time and again resort to heinous activities, indiscriminate shootouts killings, etc. and indulge in desecration of religious places besides holding armed communal demonstrations, etc."

"All these are our sensitive border areas and this adds to the anxiety of national patriotic people."

We feel proud of such intelligentia who are acting in this way who can call a spade a spade. Therefore, I am sure if proper initiative is taken from the Government side once again that can encourage all these forces and thye can fight for keeping Punjab united, maintain communal unity and make us proud of the Punjab for which the entire nation is

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर): पंजाब के बारे में श्री निहाल सिंहवाला ने बहुत कुछ कहा है । मैं उससे ज्यादा अपने ख्यालात नहीं रख सकता । जो भी कहा है ठीक ही कहा है। उनके मुंह से ऐसी बातें निकलें तो अच्छा रहता है क्योंकि मैं तो सिख नहीं हूं और मुझे अकालियों के मुतल्लिक कहना अच्छा भी नहीं लगता है । जहां तक डिमान्ड का ताल्लुक है, सभी ने कहा है कि धार्मिक डिमांड मान ली गई है। मुझे कहने में खुशी होती है कि हमारी Beloyd Leader श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अकालियों की धार्मिक डिमांड मान ली है ।

अब रह गई हैं पोलिटिकल बातें, जिनके बारे में पोलिटिकल तौर पर ही सोचना चाहिए । हम 12 कांग्रेस (आइ) एम पी. यहां पर हैं । हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात मान ली जाएं, तो ठीक है क्योंकि हम मैजोरिटी में हैं अगर नहीं मानते तो हमारे कहने का क्या फायदा है ...(**व्यवधान**)...

जहां तक रिलीजियस डिमांड का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि जो रिलीजियस पर यकीन रखता हो, उसके सामने कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती ।

Do not quarrel about religion
All quarrels and disputation concerning religion simply show that spirituality is not present. Religious quarrels are always over the husk. When Purity and Spirituality go leaving the soul dry, quarrels begin not before . . . . .
(Swami Vivekananda).

हरियाणा या राजस्थान हमारे दुश्मन नहीं हैं । सारा हिन्दुस्तान हमारा है, रिलीजियन का नाम नहीं लेना चाहिए। सिर्फ महात्मा गांधी रिलीजियस माईंडिड थे और लड़ाई करते थे और इसलिए इन्सानी तौर पर सबसे ऊंचा उठ गए । अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी जो आदमी सोसाइटी से कम लेता है और वापस ज्यादा देता है, अगर कोई परमात्मा इन्साफ करने वाला है, तो वह सबसे आगे बढ़ेगा। इसलिए जो हरिजन हैं वह भविष्य के लीडर हैं । यह कहना कि हमें यह दे दो, वह दे दो, ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि रिलीजियस का नाम नहीं लेना चाहिए । यह ठीक है हुकूमत सब चाहते हैं। जो लोग अन्जान हैं, डेमोक्रेसी का पता ही नहीं हैं, उन्हें एक्साप्लायट किया जाता है और इस तरह कामयाब हो जाते हैं । ...(**व्यवधान**)...

हिन्दू जाति के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । आसाम वाले क्यों नहीं हिन्दुओं को एक्सप्लायट करते । यह आप लोगों को समझ लेना चाहिए । यह समझदार काम है, काबू में नहीं आती है । अगर आप मुसलमान या सिख बन जाएं तो काम बन जायेगा । ...(**व्यवधान**)...

मुझे सब पता है । उस वक्त जब 1966 में कांग्रेस वाले पंजाबी सूबे की डिमांड लेकर गये थे तो अकालियों ने बाईकाट किया था और दूसरी पार्टियां गई थीं ये पोलिटीकल डिमांड को मानने के लिए अब भी साथ

[श्री सुन्दर सिंह]

नहीं देते । मामला साफ है, उन्हें पावर चाहिए और कुछ नहीं । हरियाणा हरियाणा वालों ने नहीं बनाया, इनकी तो डिमाण्ड ही नहीं थी। वह तो मास्टर तारा सिंह बना गया और इनका काम बन गया । उस वक्त युनाईटिड पंजाब में हरियाणा के दो मिनिस्टर बनते थे और उनके ही कपड़े साफ होते थे । अब तरह तरह के कपड़े पहनते हैं । इनको चिन्ता है कि सिखों के साथ बेइन्साफी हो रही है । लेकिन हरिजनों के साथ जो बेइन्साफी हो रही है उसकी किसी को चिन्ता नहीं । हमारी 15 करोड़ की आबादी है । जब पंजाबी सूबा बना तो हरियाणा अलग बन गया और अब जब खालिस्तान बनेगा तो हरिजनों को उसी तरह से 4, 5 जिले पंजाब में मिल जायेंगे और पूरे देश में आबादी के लिहाज से हरिजनों के 4, 5 सूबे हो जायें तो हमें बंसी लाल और भजन लाल के मातहत रहने की जरूरत नहीं रहेगी । अगर आपको डिवाइड ही करना है तो उसमें तो हमें फायदा है । हमने डिवीजन की बात नहीं की, जूते पड़ते हैं फिर भी आपके साथ ही रहें । आप तो बाहर से आये और हम पर कब्जा करके हमें अकेले दिया, हमें बेघर बना दिया । इसलिये सीधी बात यह है गरीबों का नाम लेते हो और हरिजनों को एक्सप्लायट करते हो । गरीबों का क्या कोई काम करता है ? काम करना बड़ा मुश्किल है । महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, उसकी तरह काम भी तो करो । केवल हरिजनों के वोट लेने के लिये उनकी बातें करते हो । अपोजिसन केवल अपोजिसन के लिये नहीं होनी चाहिये, जो अच्छी बात है उसको सपोर्ट भी करना चाहिये । अपोजीसन की तरफ से बहुत अच्छा बोले थे डा. कर्ण सिंह और श्री चन्द्रजीत यादव । बहुत शानदार बोले हैं । ऐसे अच्छे सुझाव दिये हैं जो यहां कोई देने वाला ही नहीं है । जो पॉलिटिकल फैसला करना है सारी पॉलिटिकल पार्टिज को मिल कर करना चाहिये । इन्दिरा जी ने जो पहले फैसला किया वह अच्छा है, और बाकी का भी सब को मिलकर पॉलिटिकल तौर पर करना चाहिये । हमें क्या? पानी के झगड़े से क्या ताल्लुक हमारी तो कोई जमीन ही नहीं है । हमें पानी का क्या करना है ? हरिजनों के पास न जमीन, न आसमान, न दुकान, न मकान, भारत माता जिन्दाबाद । हमारी भारत माता है ही नहीं, फिर भी हम कहते हैं कि भारत माता जिन्दाबाद । मैं एक बात बतलाना चाहता हूं --
who will be leader of the future

लीडर वह होगा जो सोसाइटी से कम लेगा और ज्यादा देगा । जो अच्छा व्यू देगा । हम हरिजन लोग हैं जो सोसाइटी से कम लेते हैं, कम खाते हैं और ज्यादा देते हैं इसलिए हम फयूचर के लीडर होंगे । जो मर्जी आप कर लें, हमने हिन्दुस्तान पर छा जाना है और जब हम हिन्दुस्तान की हकूमत के मालिक हो जाएंगे तो यह तमाम झगड़े फौरन निपटा देंगे । अभी तो हमें कोई पूछता ही नहीं है । हम बाद में कहेंगे कि हमारी जगह है, हम फैसला करेंगे ।

आपको चाहिये कि लिफ सिम्पैथी नहीं होनी चाहिये, बूट पालिश नहीं होनी चाहिये । मैं शिडयूल्ड ट्राइब्ज कास्ट कमेटी का मेम्बर हूं, मैंने देखा है कि
में कोई इम्पली-मेंटेशन नहीं होता है । पता नहीं हरिजनों ने मर जाना है या क्या करना है ।
Reservation in promotion

जो आदमी किसी को धोखा देता है, वह खुद धोखे में आ जाता है मैं इस चीज को मानता हूं --

I prefer to be cheated by others than to cheat others

(Swami Vivekanand)

जो आदमी किसी को धोखा देता है, वह खुद धोखे में रहता है । जब हम परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा फैसला करेगा। हम सबसे कम लेते हैं, सबसे कम जायदाद हमारे पास है और चौधरी आप बने हुए हैं । यह बेइन्साफी हुई है । महात्मा गांधी बेइन्साफी बर्दाश्त नहीं कर सकते । जो काम आज हमारी इंदिरा जी कर रही हैं, इस वक्त वह डिफीकल्ट वक्त में चल रही है। अगर आप उनकी जगह होते तो आपका बुरा हाल होता और आप कामयाब नहीं हो सकते । आप को अच्छे काम में इनका

साथ देना चाहिये । हिन्दुस्तान मूर्ति-पूजा का देश है । इंदिरा जी के खानदान पर लोगों का विश्वास है, मैं और आप इसमें क्या करेंगे ? उनके पास वह चीज है जिस पर लोग यकीन करते हैं । अगर किसी को यकीन ही न हो तो--

He who has faith has all,
who lacks faith, lacks all,
It is faith in the name of
the Lord that works wonders
And faith is life,
Doubt is death.

(Swami Vivekananda)

हम एक लीडर पर विश्वास रखते हैं : वह है श्रीमती इंदिरा गांधी । अपोजिसन के कई लीडर हैं, इसलिए कमजोर है । अगर अपोजिशन मजबूत हो तो गवर्नमैंट ज्यादा मजबूत हो जाती है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके लिये अगर कोई बात मुझ से ऐसी निकले जो किसी वर्ग या पक्ष को अच्छी न लगे तो उसके लिए वह मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन सत्य यह है कि पंजाब में जो कुछ रहा है या जिस स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, वह लक्षण है, रोग नहीं है, सिम्पटम हैं, डिसीज नहीं है ।

यह लक्षण क्यों पैदा हुआ ? जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने संविधान बनाया तो उन्होंने केन्द्र और प्रदेशों के बीच में हक का बंटवारा किया । बदकिस्मती से प्रदेश, जिला से गांव के बीच में हक का बंटवारा नहीं हुआ । यह मूल दोष उसमें रह गया। जो बंटवारा हुआ है, उसका तजुर्बा यह है कि जो वित्तीय संसाधन हैं उसकी वसूली जब केन्द्र करता है तो उसका रेट देख लीजिये और जिन संसाधनों का बंटवारा राज्य और केन्द्र में होना है, उसकी वसूली अगर आप दिखवा लें, तो बंटवारे वाली धनराशि की वसूली उतनी नहीं है जितना उस संसाधन का प्रतिशत है जो सिर्फ सेन्टर को अपने पास रखना है । उसी तरह जनता से चुनी हुई असेंम्बलियों को सन 1960 और उसके बाद कई बार तोड़ा-मरोड़ा गया । कुछ भाई कहते हैं कि जनता पार्टी ने भी ऐसा किया, उसके मायने यह नहीं कि इस बात में दोष नहीं रह गया । अगर जनता पार्टी इस तरह की अक्षम्य भूलें न करती तो जाती भी नहीं उसका जाना ही इस बात का सबूत है और उधर का वहां आना ही सबूत है कि लोग इस तरह के रवैये से परिवर्तन चाहते थे । लेकिन सत्ता पक्ष जनता पार्टी की ही तरह से और अपनी भी पूर्ववर्ती चलन कायम रखना चाहता है तो मुबारकबाद; उसके जाने में देर भी नहीं लगेगी, हमें इस पर और कुछ कहना नहीं है ।

सवाल यह है कि 1966 में हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ राजधानी का प्रश्न उसी दिन आपने क्यों नहीं हल किया, सारे प्रश्नों का हल उसी समय क्यों नहीं निकाला ? 1967 के चुनावों पर नजर डाल कर एक फैसला कर लिया । 1966 से लेकर 1977 तक कौन था राज्य और केन्द्र की सरकार में ? बहस के लिए मान लिया कि तीन-पौने तीन साल एक खराब सरकार आ गई लेकिन 1966 से 77 तक हरियाणा और चण्डीगढ़ का फैसला आपने क्यों नहीं किया ?

केन्द्रीय सरकार ने 1977 तक, अबोहर और फाजिल्का का जो फैसला प्रधान मंत्री का था, उसको लागू न करके इस बात को मान लिया कि प्रधान मंत्री का फैसला गलत था । अगर वह फैसला गलत था तो उसकी वजह से आज रोग उभड़ रहा है। पौने तीन साल की बदकिस्मत जनता पार्टी की सरकार के ऊपर सारा दोष देने से यदि आपको खुशी होती है, सवाल हल होता है तो दोष दे दीजिए । लेकिन उसके बाद 1980 से पूर्ववर्ती सत्ताधारी दल फिर मौजूद है अब जाकर आपको याद आया कि चांदनी चौक का गुरुद्वारा कोतवाली से वापिस करना चाहिए । कितने सालों के बाद अब सत्तारूढ़ दल को और सरकार को याद आया कि सिख क्या मांग रहे हैं । एक सबसे खराब बात जो है वह मैं सरकार और विरोधी पक्ष से भी कहना चाहूंगा कि आप कभी यह बात न कहें – सिख, सिख, सिख

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

का सवाल है । अकाली पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है । इसके पीछे अगर सभी सिख न भी हों तो भी बात रह जाती है वह एक पॉलिटिकल पार्टी है इस देश की पालिटिक्स में जात धर्म के एविरेशन्स हैं, क्या यहां इंडियन यूनियन मुस्लीम लीग नहीं है ? यही एविरेशन्स, एक टेढ़ापन आ गया है हमारी सियासत में । कोई नजर चुराकर आप कह दें कि वह कोढ़ी नहीं है, लेकिन कोढ़ी तो है, शीशे में देखेगा अपना चेहरा पता लग जाएगा, इसलिए अकाली पार्टी एक रियलिटी है । हमारे दोस्त कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के सभी लोक सभा में जीत कर आ गए । हमने सब जीतकर भी देखा है और सब हार कर भी देखा है और अब वह वक्त दूर नहीं है जब फिर देखना होगा अगर आपकी प्रधान मंत्री ने जल्दी कर दी नवम्बर जनवरी में भी और हम तो मना रहे हैं कि वे जल्दी कर दें . . (व्यवधान) . . हम तो कभी निराश हुए नहीं हैं, निराशा आपके ही हिस्से में है हम तो आशा से बराबर जिए हैं । स्वराज की लड़ाई में आशा से आए थे और आज भी आशा पर जीवित हैं । हम तो इस बात को मानकर चलते हैं कि सारे निकम्मेपन के बावजूद यह देश बलवान और शक्तिशाली है और इस देश के रहने वाले मजबूत हैं । मैं पंजाब के गांव गांव में घूमा हूं, सिख कहीं भी नहीं कहते हैं कि हिन्दुओं को मार दो । यह झूठ बात है । जब कोई एक आदमी मारा गया तो क्यों सरकार रेडियो पर कहती है कि सिख ने हिन्दू को मारा? मैं आपके द्वारा इस सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह अपनी मीडिया को ठीक करे, उसका दुरुपयोग न होने दें। सत्ता पक्ष को खासकर समझदारों की बात बोलनी चाहिए । अगर सरकार को उनकी रिलिजस डिमाण्ड्स माननी ही थी तो गुरुद्वारे में जाकर क्यों मानी ? अगर सरकार इस सदन में एलान नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी नजर में इस सदन का कोई महत्व नहीं है तब आप आज यहां क्यों कहते हैं कि बड़ा भारी सीमान्त प्रश्न है? हमारे चौधरी सुन्दर सिंह तो और भी एक कदम आगे चले गये। उन्होंने कह दिया अकालियो देखो, हम तुम्हारी नकल नहीं करना चाहते हैं नहीं तो इस देश का एक चौथाई अछूतिस्तान बना सकते हैं । इन बातों को कहना ही स्वयं में अपराध है । इस तरह की बातों से दिमाग बटते हैं और एक तरह की जहनियत बनती है । सदन में जो बोला जाता है उसका बड़ा भारी महत्व है। मेरा तो बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है कि हिन्दुस्तान के सिख झगड़े पर उतारू हैं । या उनकी शैतानियां हैं कि खालिस्तान बने। क्या हमारे यहां डाकू नहीं हैं तो, फिर सब हिन्दुस्तानी डाकू हो गए। मोहर सिंह या फूलन देवी को मंच पर आप माला पहनायें, फिर भी हिन्दुस्तान डाकू नहीं है । अगर चार सिख नौजवान गड़बड़ करते हैं और जहाज को उड़ा कर ले जाते हैं तो ठीक है, अकाली दल को इसे बहुत बुरा बताना चाहिए था । लेकिन यह परम्परा बन गई कि कुछ लड़कों ने जहाज उड़ाया तो उस तरफ से किसी ने बुरा नहीं बताया कि बुरा कर रहे हो । इंदिरा जी का उस पर एक बयान नहीं है कि इन लड़कों ने गलत काम किया है । उल्टे उनको एम. एल. ए. बना दिया । महाजनों एनगतः सपन्थाः--श्रीमान जी, बड़े लग जिस रास्ते पर, बड़ी पार्टी जिस रास्ते पर चलेगी अन्य लोग उस रास्ते को नकल करेंगे। इन छोकड़ों ने सोचा कि वे जहाज उड़ा कर ले गए, लखनऊ से बनारस तक तो एम. एल. ए. बने । इन्हों ने सोचा कि हम लेकर चलें लाहौर तो हमारा राज्य या गया तो विदेश मंत्री बनेंगे एक और राप्ता जुड़ेगा । इस घटना को लेकर आज रो रहे हैं। रोपयो पेड़ बबूल को, आम कहां ते होए--क्या बोया है सत्ता दल ने? इसलिए आज को भूलिए, कल की बात करो। रह गई पानी और चण्डीगढ़ की बात। चण्डीगढ़ जाना होगा पंजाब में पानी के मामले को आप दिखवा लीजिए । वे कह रहे थे कि दिखवा लीजिए । लोकतंत्र में अंतिम बात कोई नहीं होती है. फिर-फिर विचार हो सकता है--दिखवा लीजिए । हां—तेल निकला असम में, तेल निकला गुजरात में तो रायल्टी ड्यू हो जाएगी । पानी निकला हिमाचल से और सब बंटवारा कर रहे हैं । हमारे यहां पूरी

उत्तर प्रदेश में एक कहावत है--फलानां वन बांट लिया राजा को पता नहीं—इसके आगे मैं नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें जाति—विशेष का नाम आता है । पानी बांट लिया हिमाचल को पता ही नहीं है । हिमाचल को रायल्टी क्यों नहीं दोगे ? वह गरीब स्टेट है । भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश को क्या देना है।

श्री भीमराम जैन : एक बात और नई आ गई ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जरूर आएगी, वह मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि नया भारत चलता रहेगा और पिछड़े लोग, पिछड़े इलाके हमारे गरीब गावों का किसान मुंह देखते रहेंगे, ये भारत के खतरे हैं, न खालिस्तान खतरा है और न जगजीत सिंह खतरा है। एक जगजीत सिंह नहीं है, भारत में खुदीराम से लेकर भगत सिंह तक बहुत लोग हैं, जिसका नाम हमें ताकत देगा। पर अकाली दल किसका नाम ले रहा है? पंजाब हमारी सांस्कृतिक, राजनीतिक चेतना की जन्मभूमि है, वहां कहां गड़बड़ होने वाली है ? चाहे कोई कुछ भी कर ले । लेकिन, हां सब लोग कह रहे हैं कि सूबे को आटोनामी दो । तो करो । मैं कहता हूं कि इस बात को खुद प्रधान मंत्री कहती तो बहुत अच्छा होगा ।

मैं मान्यवर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार तब जागती है, जब टाइम नहीं रह जाता है । तीन साल से क्या कर रहे हैं? 1980 से आ गए, 1983 हो रहा है और अब जाने का समय नजदीक है । अंत में मैं यह कहता हूं सेठी जी जाने के पहले कुछ कर लो, वरना फिर पछताए होत क्या जब चड़िया चुग गई खेत'' ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि बातचीत के द्वारा सब बातों को समझ कर, अपनी भूलों को स्वीकार करते हुए नया भारत को बनाने के लिए, नई मान्यताओं की स्थापना के लिए काम करेंगे ।

SHRI CHIRANJI LAL SHARMA (Karnal): Mr. Deputy-Speaker, Sir, there has been a lot of discussion on this delicate problem. The discussion was started by Atal Bihariji on the 4th of November. Sir, it is good that a period of two to three months has since elapsed. The Charter of Demands which began with 44 has been reduced to two. according to Shri Atal Bihari Vajpayee.

Sir, how did Punjabi Suba come into being? It has been very beautifully put by Choudhury Sunder Singh. Haryana did not demand it. The rights of the Haranavis, the present Haryana, were being ruthlessly trampled under the iron feet of the then Punjab Government. Haryana was being treated just as a colony. We were being treated just like dumb driven cattle. And Punjab came into being when, Master Tara Singh, Giani Kartar Singh, Sant Fateh Singh, the old Akali leaders pressed for it. Punjab lost and lost considerably. Haryana gained and gained materially and Himachal is all gold. As was rightly put by my friend Sardar Gurcharan Singh, Gurumukhi and Punjabi were taught all over the State of erstwhile State of Punjab. Haryana was a part of it. What did Haryana lose?

Now the question is: After Haryana came into being, are the rights of Haryana being safeguarded? That is the point. There are two issues before the House. One is the territorial question; and the other is about Ravi-Beas dispute. First of all, I take up this territorial question. When there was a demand for Punjabi Suba, Government of India constituted a one-man Shah Commission. According to the report of Shah Commission, Chandigarh was given to Haryana; and with your permission, Sir, I refer to paragraph 135 of that report. The four-line recommendation is dated 31st May 1966. It says:

> "That districts Hisar, Mohindergarh, Gurgaon, Rohtak and Karnal and Tehsils Narwana and Jind (District Sangrur) and Tehsil Kharar (including Chandigarh capital project), Naraingarh, Ambala and Jagadhri will form the
>
> Hindi-speaking State of Haryana."

This is the recommendation. The whole House may not be aware of it. I was a member of the Assembly those days; and I was very much in the thick of things

(Shri Chiranji Lal Sharma)

Now, the Shah Commission gave Chandigarh to Haryana. After the recommendations of the Shah Commission, the then Akali leader Sant Fateh Singh threatened to immolate himself. Preparations were set afoot, as was remarked by Sardar Gurcharan Singh, though not in right earnest. It was just to throw mud into the eyes of the people and to force the Government of India, and to compel the Prime Minister to accede to their request. And the Shah Commission's recommendations were modified. The Prime Minister or, say the Government of India gave a decision that Chandigarh minus seven villages contiguous thereto would go to Punjab; and the railway station of Chandigarh would go to Haryana. At the same time, Abohar and Fazilka constituting 114 villages would go to Haryana. Now they say: "Why Abohar and Fazilka should go to Haryana?" When Chandigarh was given to Haryana by the Shah Commission, and the Shah Commission's report was further modified, this condition was precedent. I say: 'Let Chandigarh go to Punjab; but with the same stroke of pen, and at the same time, Abohar and Fazilka must come to Haryana. This is the decision.

Now why is this not being implemented? My friend, Shri Bansi Lal is here. He has been the Chief Minister. He wrote letters to the Prime Minister, not once but twice, requesting implementation of her award. Who is to blame? Are we to blame? Rs. 20 crores were to be given to Haryana for the construction of a capital for Haryana. It was not given. Was the delay in implementation our fault? Are we to be found fault with? Can I have the temerity to ask the Akali friends, through you Sir; what about the 33 months during 1977—1979 when the Akalis were holding the reins of power in Punjab. Prakash Singh Badal was guiding the destiny of the State; and they were partners in the Central Government also, in the Government headed by Morarji Desai. Atal Bihari Ji was holding a very important portfolio in that Ministry. Atal Ji has very sarcastically or ironically or in a laughing way remarked: "As along as we were there, there was no problem." May I ask Atal Ji a plain question: "Was there no question of implementation of that award then? Was there no question of handing over Chandigarh to Punjab?" Because they did not want that it should crop up at that time. Atalji has said, "There was no cry for Khalistan at the moment." Shall I have reasons to smell a grain of doubt in their *bona fides?* Are they instigating them now? Why did they keep mum for about three years? Now they come with demands.

16.00 hrs.

Haryana is very particular about it. We had represented our case and the case had been discussed at length. My Akali friends want to get Chandigarh and not part with Abohar and Fazilka; this cannot happen. Probably, they are labouring under an illusion. Choudhary Sunder Singh sarcastically remarked that, "these Haryana people, we used to give them, the *chiti* dhotiwalas as Ministers." He rightly said so. Our mouth was gagged by inducting two persons as Ministers in the Cabinet. Budget was passed, but that budget was utilized in areas beyond Ambala. He said about it rightly. I do not take exception to his observation, because this was the treatment that was meted out to us; we were so shabbily treated; and he says now that we are moving in cars and all that.

I had read the Report of the Shah Commission; it was modified under a threat of immolation. If Chandigarh is to go, both Abohar and Fazilka should come.

Regarding Ravi-Beas dispute, I want to invite the attention of the House to the recommendations of Committees and Planning Commission regarding sharing of Ravi-Beas Waters, because all the hon. members may not be aware of this—Four committees were appointed—They read as follows:

"*Food Committee*

An expert Committee called the Food Committee on land and water use in Punjab was constituted on 12.1.65 to recommend rational distribution of the surplus Ravi-Beas waters in the State.

The Committee recommended during February, 1966 that 4.56 MAF of waters be allocated for the areas now forming the State of Haryana.

Fact finding Committee April 1970

Government of India constituted a Comittee during April, 1970, for collecting facts regarding river flows, existing utilization of waters and capacity factors in the States of Punjab and Haryana and such other facts as are relevant for discussion leading to the determination of the shares of the respective States. The Committee accordingly collected the above data and sent it to Government of India. The Committee recommended that 3.78 MAF should be allocated to Haryana. The case then remained under corresponence between the Govt. of India and the States of Punjab and Haryana but no decision was arrived at.

Planning Commission Note of March 1973

In March, 1973, a note for the allocation of erstwhile Punjab's share of surplus Ravi-Beas waters between the reorganised States of Punjab and Haryana prepared in the Planning Commission, was handed over to the Chief Minister of Punjab. In this note, an allocation of 3.74 MAF, on the basis of the availability of surface and ground waters was suggested for Haryana. Meetings to sort out the shares were also held but both the States were not satisfied. Haryana was claiming 4.8 MAF whereas Punjab was stressing to reduce share of Haryana suitably.

Chairman, Central Water Commission's Report

In 1974, the Chairman, Central Water Commission was asked to examine *de novo* the technical aspect of the problem relating to the sharing of surplus Ravi-Beas waters between Punjab and Haryana. In this report he recommended sharing of Beas Project Waters on 50:50 basis."

I have read before the House the recommendations of the four committees. Even 3.5 MAF was given to Haryana; that should not be given. We are claiming that we should get it.

On the 31st December, 1981, an agreement was arrived at between the Chief Minister of Punjab, Sardar Darbara Singh Chief Minister of Haryana, Shri Bhajan Lal, and the Chief Minister of Rajasthan, Shri Mathur, in the presence of the Irrigation Ministers and the Prime Minister. Three Chief Ministers are signatories to this agreement.

Now, Punjab is estopped by its own conduct under Section 115 of the Evidence Act from taking this plea. Well, they do not want to stick to it! Mr. Deputy-Speaker, these are not agreements arrived at, between two individuals. When Sardar Prakash Singh Badal signed it, he did not sign it in his individual capacity. He signed it as the Chief Minister of Punjab. He signed it as the representative of t he people of Punpab; and now does it lie in the mouth of my Akali friends to say, "Well, we do not stick to it."? They may not. They want to get power under the threat of bayonet, under the threat of going on strike, under the threat of creating problems all over the country. But I may tell them with all humility that Prime Minister Indira Gandhi is not a lady to be cowed down by threats. She cannot be cowed down. It has been rightly suggested by my friends: Let there be mutual discussion in a healthy atmosphere, as there has been so far. Now, this agreement of the 31st December was arrived at when the then Law Minister, Shri P. Shiv Shankarji had given seventeen sittings to both the parties and it was after months of deliberations that they came to certain conclusions. Now, they want to side-track the issue. These are the two main issues. In this very connection, I want to—I will not take much time—tell the House as the House may not be knowing it, that land was acquired by the Government of Punjab during the days of Prakash Singh Badal. I can give the date and the number of the notification under which the land of three villages was acquired, about 120 acres of land. Haryana advanced Rs. one crore, *vide* Memo. No. 9830-IPW dated 10-11-1976. Then again when Prakash Singh Badal was the Chief Minister, Haryana advanced another Rs. one crore *vide* Memo No. dated 30-3-1979. Haryana again advanced

[Shri Chiranji Lal Sharma]

Rs. two crores on 25-1-1982, Rs. 4 crores on 4-3-1982, Rs. 7.50 crores on 26-8-1982 and Rs. 5 crores on 20-10-1982. The land was acquired by the then Chief Minister, Sardar Prakash Singh Badal, who says, now, "We do not stick to it". But then there are proceedings in the files, in the offices of both the Governments of Haryana and Punjab, that the foundation stone would be laid by Sardar Prakash Singh Badal and that the Chief Minister of Haryana would be presiding over the function. This is nothing—as was rightly demanded by Sardar Gurcharan Singh—but a cry for power. Let these Akalis be given an opportunity to replaces the present Chief Minister and the prensent Government, let them be in the saddle by hook or crook, the whole matter will subside. Do you think, that the unity and solidarity of the country can be allowed to be disturbed under these circumstances? What has been happening in the past? Do my firends want that the same history should be repeated in Punjab and that Haryana should keep mum? No. It does not mean that we can be cowed down.

So, I would respectfully suggest—as has been suggested by my friend Shri Atal Bihari Vajpayee—that these solutions can be found, by mutual deliberations and by sitting round the table and not by threats. The problem is not so delicate as is being made. This is being made delicate. For the last one year they have been raising all hue and cry when there was nothing serious.

The Sikhs are a brave people. They have made great sacrifices. It is not a question of Hindus or Sikhs. It is a question of cry for power by Akalis and nothing else. With these words, I conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Chitta Basu. You have to be very brief.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): I rise only to address and appeal to the Government and also to the parties concerned in the Punjab tangle, to adopt an attitude of constructive cooperation so that the tangle can be solved as early as possible. While making an appeal of this nature I should also point out to the House that the question which has given rise to the Punjab tangle, has been on the basis of certain demands.

Demands relate to territorial adjustment, just and equitable distribution of the waters of Ravi and Beas and re-structuring or re-shapping the Centre-States relations. Demands also relate to certain demands of the Sikhs as an important minority community of our country. If you kindly go through the nature of the demands, I think, the House will agree with me that the demands are not the demands of any particular community, whether Hindus or Sikhs. But the demands are the demands of the people of Punjab as a whole, whether they are Sikhs or Hindus or belong to other communities. Therefore, in respect of these demands, I would say that these are all democratic demands. These demands are to be discussed. Viewed from the point of view of democratic norms, these should not be treated as demands of one particular community. directed against another patricular community. Instead of having that approach to the problem, there has been some slant towards communalism which poses danger to the country as a whole. Naturally, if this kind of a movement or agitation is not properly tackled or handled and the just and democratic demands or aspirations of the people are not conceded quickly, the extremists, parochial, sectarian and communal forces will take advantage of this situation. I think, I will not be wrong if I say that due to tactless handling of the situation by the Government and delay in working out a political solution to the problem in a democratic manner, some extermist elements, who are now working in Punjab, have taken advantage of the situation. Naturally, a political solution should be worked out as early as possible so that the extermist elements which are in the agitation, can be isolated from the broad masses of the Punjab people. Having this perspective in view, I would urge upon the Government that immediate steps should be taken so that the just and democratic demands of the people are conceded as early as possible.

I had the opportunity of joining the tripartite meetings towards the end of the

discussion and to my great satisfaction, I found that there was a climate conducive to mutual discussion and coming to an agreed solution of the problem. As a matter of fact, the area of agreement between the Central Government and all other parties involved, has been minimised. Rather the area of agreement is wider than the area of disagreement. In this particular situation. I would request the Government to take immediate steps to see that negotiations, tripartite or bipartite, are started as soon as possible and solution are worked out for that particular area where these agreements still exist. I would also appeal to the leadership of Akalis that instead of pressing for the resignations, they should also corporate in the larger interest for bringing about a political solution of the democratic demands and for furthering and strengthening the national unity and integrity of the country From the side of the Opposition it has been mentioned that in order to bring about that kind of a workable solution, on the basis of just principle, there would be no dearth of cooperation from this side. But if somebody wants to take a partisan position, if somebody wants to take a position by which he wants to derive benefit but of this politically, naturally, Sir, you cannot expect that the Opposition parties should fall into their prey. Naturally, therefore, it is not a point of intrigue. It should be an open statesmanship by which this kind of problem can be solved through mutual discussion and through constructive cooperation. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now the Minister will reply.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. C. SETHI): Sir, I am grateful to the hon. Members who have participated in the debate. As I could understand, the sentiments expressed here are one and unanimous that the Punjab tangle should be resolved through negotiations. I am very happy that an appeal by Shri Atal Bihari Vajpayee and others has also been made to Akali leaders to agree to start the negotiations again. As far as the situation in Punjab is concerned, we are still in the process of some form of negotiations and, therefore, I would be making a very brief statement.

As the House is aware, Government have been making earnest efforts to consider a fine solution to the demands of the Shiromani Akali Dal. Extensive discussions have been held with the representatives of the Shiromani Akali Dal. In the last few rounds of the discussion, the leaders of Opposition parties in Parliament as well as the Chief Ministers and Opposition in Parliamen t for their par-Rajasthan have been associated. I must express my thanks to the leaders of the Opposition in Parliament for their participation and their valuable contribution to tripartite talks. Our effort has been to understand the viewpoint of all the concerned parties. Government have always been sympathetic to the sentiments and interests of all communities. Hon. Member would appreciate that solution to any demands and grievances has to be found, keeping in mind the larger national interests. The Governmnet have accepted the religious demands of the Sikh community. The questions of sharing of the waters of Ravi-Beas and territorial adjustments concern other States also. These issues have been discussed with the Chief Ministers and the leaders of the Opposition of the concerned State and also in tripartite talks. The Government's constant endeavour is to arrive at a solution acceptable to all and efforts in this direction are continuing. I will earnestly make an appeal to all concerned through this House that we should continue to seek a solution through negotiations acceptable to all and not do anything which may precipitate the situation. In a democracy, negotiations and spirit of accommodating each other's point of view are the only way by which solutions can be found. From our side, we shall always be conciliatory and we will keep our doors always open for talks. We believe in resolving problems through negotiations but the solution of one problem should not give rise to problems. We will continue to seek solution in this spirit and we will continue to solicit the help and support of the Opposition leaders and parties to find an amicable solution.